राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 29 मार्च 2026 वर्ष-9,अंक-63 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

रूस ने 4 महीने के लिए पेट्रोल निर्यात रोका

- 1 अप्रैल से लागू, भारत पर कम, चीन-तुर्किये और ब्राजील पर ज्यादा असर

मॉस्को (एजेंसी)। रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। उप-प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा। रूस के मुताबिक यह कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए है। नोवाक ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल-ईरान जंग की वजह से ग्लोबल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल

निर्यात करता है। इस फैसले से चीन, तुर्किये, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर प्रभावित हो सकते हैं। ये देश रूसी तेल उत्पादों के बड़े खरीददार हैं। भारत पर असर कम होगा क्योंकि वह पेट्रोल नहीं, कच्चा तेल खरीदता है। मॉस्को में शुक्रवार को पेट्रोल एक्सपोर्ट के बैन को लेकर बैठक हुई थी। इसमें खासतौर पर यह जोर दिया गया कि राष्ट्रपति पुतिन ईंधन कीमतें नियंत्रित रखना चाहते हैं। मंत्री नोवाक ने बैठक में कहा कि पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। तेल कंपनियों ने कहा कि पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और रिफाइनरियां पूरी या उससे अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे जरूरत पूरी हो रही है। रूस पहले भी कीमत नियंत्रण और घरेलू सप्लाई के लिए पेट्रोल-डीजल निर्यात पर रोक लगा चुका है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, जब यूक्रेन हमलों से रिफाइनरियां प्रभावित हुई थीं। इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, रूस ने पिछले साल करीब 50 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल एक्सपोर्ट किया था, यानी हर दिन लगभग 1.17 लाख बैरल के बराबर है। एक दिन पहले ही नोवाक ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो रूस फिर से तेल निर्यात पर रोक लगा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि रूस का यूराल्स तेल और दूसरे तेल उत्पाद इन दिनों महंगे दाम पर बिक रहे हैं।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिले एस जयशंकर

- विदेश मंत्री ने पहुंचाया पीएम मोदी का 'स्पेशल मैसेज'

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों जी-7 ग्रुप की बैठक में शामिल होने के लिए फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। जयशंकर ने इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की और पीएम मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दीं। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शनिवार को पोस्ट कर बताया कि बैठक बेहद सकारात्मक रही और विभिन्न वैश्विक व द्विपक्षीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने

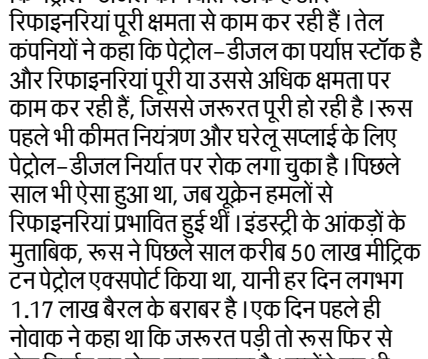

पोस्ट में लिखा, कल रात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। मैंने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिवादन दिया। चर्चा और उनके बहुमूल्य विचारों का मैं आभारी हूं। वहीं ने गुरुवार को फ्रांस में आयोजित जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों, शांति स्थापनों के अभियानों को सुव्यवस्थित करने और मानवीय सहायता आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर प्रकाश डाला। जयशंकर ने फ्रांस में वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार के विषय पर साझेदारों के साथ हुई बैठक में भाषण दिया।

जयशंकर ने उठाया ऊर्जा संकट का मुद्दा

जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, वैश्विक शासन में सुधार पर आमंत्रित साझेदारों के साथ जी 7 विदेश मंत्रियों की बैठक के सत्र में भाषण दिया। यूएनएससी में सुधारों, शांतिरक्षा अभियानों को सुव्यवस्थित करने और मानवीय सहायता आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर प्रकाश डाला। पोस्ट में लिखा, खास कर वैश्विक दक्षिण की ऊर्जा चुनौतियों, उर्वरक आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उठाया गया।'

पाक-बांग्लादेश बॉर्डर पर एंटी-ड्रोन से निगरानी

- चीन सीमा पर 3 गुना बढ़ी पेट्रोलिंग, अभेद्य हुईं भारत की सरहदें

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और गलवान झड़प के बाद अपनी सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। ड्रोन घुसपैठ और सीमा पार की चुनौतियों को देखते हुए भारत अब पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर एंटी-ड्रोन, सेंसर और लेजर की मदद से निगरानी शुरू कर दी है। वहीं, लद्दाख में चीन बॉर्डर पर 29 नए आउटपोस्ट बनाने के साथ भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की पेट्रोलिंग 3 गुना बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय की ऐन्यूअल रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक, भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर असम के धुबरी में 5-5 किमी इलाके में कंप्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के दो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। वहीं, म्यांमार सीमा पर भी नजर है।

सीमावर्ती इलाकों की मैपिंग, बॉर्डर पर बढ़ाई गई पेट्रोलिंग

पीएम गति शक्ति पोर्टल का इस्तेमाल सीमावर्ती बुनियादी ढांचे की सटीक मैपिंग और रणनीतिक योजना बनाने के लिए किया जा रहा है। पीएम गति शक्ति पोर्टल और स्पेस मैपिंग की मदद से संवेदनशील इलाकों की सटीक निगरानी की जा रही है। चीन सीमा पर आईटीबीपी ने 2022 से 2024 के बीच 29 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए हैं। जिसके बाद आउटपोस्ट की कुल संख्या 209 हो गई है। आउटपोस्ट की संख्या में बढ़ोत्तरी जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद की गई है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, 2017-18 में आईटीबीपी औसतन 173 पेट्रोलिंग प्रति माह करता था। वहीं, 2023-24 में यह संख्या बढ़कर करीब 500 प्रति माह हो गई, यानी करीब 3 गुना बढ़ोतरी हुई है।

ईरान ने अमेरिकी जहाज पर फिर बोला हमला

- सेना का था मददगार, मिडिल ईस्ट में और बढ़ा तनाव

तेहरान (एजेंसी)। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान की सेना ने एक बार फिर से अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। यह जहाज अमेरिकी सेना को लॉजिस्टिक मुहैया करवाने में मदद करता था।

ईरानी सेना ने शनिवार कहा कि उसने ओमान के सलालाह बंदरगाह के पास एक अमेरिकी लॉजिस्टिक्स जहाज पर हमला किया। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने सरकारी टीवी पर जारी एक बयान में कहा,आक्रामक अमेरिकी सेना को सहायता पहुंचाने वाले एक लॉजिस्टिक्स जहाज को, ओमान के सलालाह बंदरगाह से काफी दूरी पर ईरान की सेनाओं द्वारा निशाना बनाया गया।

सरकार ने 2.38 लाख करोड़ के रक्षा प्रस्ताव किए मंजूर

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव में आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए कई अहम सिस्टम और प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सेना के लिए एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम, आर्मर पियर्सिंग टैंक गोला-बारूद, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, धनुष गन सिस्टम और रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम को मंजूरी मिली। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 55 प्रस्ताव मंजूर कर चुका है, जिनकी कुल लागत 6.73 लाख करोड़ रुपए है। इसी दौरान 503 डिफेंस डील साइन हुई, जिनकी कीमत 2.28 लाख करोड़ रुपए है। सरकार के मुताबिक यह किसी एक वित्त वर्ष में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा खरीद और मंजूरी का आंकड़ा है। भारतीय वायुसेना के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एस-400 मिसाइल सिस्टम,रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट,ओवरहाल को मंजूरी मिली।

देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन

- नोएडा में पीएम बोले-युद्ध के संकट से देश को एकजुट होकर लड़ना है

नोएडा (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज-1 का उद्घाटन किया। यह अभी देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 4 फेज पूरे होने पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा।

पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से इजराइल-अमेरिका और ईरान की जंग से उपजे संकट से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा- कल सभी राज्यों के सीएम से चर्चा हुई। देशवासियों से कहूंगा कि धैर्य और एकजुटता के साथ इस संकट का सामना करें। ये पूरी

दुनिया को परेशान करने वाला संकट है।

प्रधानमंत्री ने कहा- देश के राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में ऐसी बातें करने से बचें, जो देश के लिए नुकसानदायक हैं। देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो गया है। इसमें करीब 3300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए हैं। यह टर्मिनल हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 11 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से दुनिया के सामने संकट खड़ा हुआ

पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। इसके चलते कई देशों में संकट पैदा हो गया है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस युद्ध-प्रभावित क्षेत्रों से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वह कदम उठा रही है, जिससे सामान्य परिवारों और किसानों पर बोझ न पड़े। 140 करोड़ देशवासी इस मुसीबत का एकजुट होकर सामना करें। नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। जब यहां सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया। तब पुराने मुख्यमंत्री (अखिलेश) इतने डरे हुए थे कि वे कार्यक्रम में आए ही नहीं। मुझे भी डराने की कोशिश की गई।

सपा ने पश्चिमी यूपी को लूट का एटीएम बना दिया था

सपा ने पश्चिमी यूपी को लूट का एटीएम बना दिया था। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनी तो जेवर एयरपोर्ट की नींव पड़ी, निर्माण हुआ और अब शुरू भी हो गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 52 स्क्वायर किमी में बनना प्रस्तावित है। पूरा बनने की डेडलाइन 2040 है। नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े अफसरों ने बताया- एयरपोर्ट से फ्लाइट मई से शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कम समय में बोर्डिंग संभव है।

दरियादिली नहीं, मेहनत से मिली है तरक्की

- चीन ने अमेरिका को सुनाया, भारत पर भी दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान के साथ युद्ध में उलझे अमेरिका पर बिना नाम लिए चीन ने तीखा तीर छोड़ा है। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने साफ कहा है कि भारत-चीन की आर्थिक तरक्की किसी बाहरी ताकत की दरियादिली का नतीजा नहीं, बल्कि अपने लोगों की कड़ी मेहनत और समझदारी का परिणाम है। उन्होंने उन दावों को सिरे से खारिज किया, जिनमें चीन की तरक्की को अमेरिकी समर्थन से जोड़कर देखा गया था। उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ के हालिया

बयान के जवाब के तौर पर देखी जा रही है, जिसमें उन्होंने चीन को दिए गए आर्थिक फायदे को गलती बताया था। 14वें चीन-भारत युवा संवाद में बोलते हुए शू ने बिना नाम लिए अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ ताकतें भारत और चीन को साथ नहीं देखना चाहतीं और चीन खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत-चीन, दोनों देशों की उपलब्धियां उनके अपने प्रयासों पर आधारित हैं, जिन्हें वैश्विक सहयोग का समर्थन जरूर मिला।

भारत-चीन जैसे देशों पर बड़ी जिम्मेदारी

शू ने दुनिया के मौजूदा हालातों को उथल-पुथल भरा बताते हुए कहा कि बढ़ता एकतरफावाद, संरक्षणवाद और दादागिरी की राजनीति, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में भारत और चीन जैसे बड़े देशों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे संवाद और तालमेल को मजबूत करें, ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा करें और दुनिया को जंगल के कानून की ओर लौटने से रोकें।

दो और 'जहाजों' ने पार किया संकट वाला रास्ता

- होर्मुज स्ट्रेट पर भारत को फिर से मिली बड़ी विजय

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत आने के लिए दो और व्यापारिक जहाज ईरान के युद्धग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजर गए हैं। भारत आ रहे इन जहाजों पर पेट्रोलियम पदार्थ लदा हुआ है। भारत आ रहे दोनों जहाजों को कवर देने के लिए भारतीय नेवी के युद्धपोतों को स्टैंडबाय मोड में तैनात रखा गया है। उम्मीद है इन जहाजों के होर्मुज से गुजरने के बाद कुछ और जहाजों को भी इसी तरह से निकलने का रास्ता मिल सकता है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट दी है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भारत के लिए पेट्रोलियम उत्पाद ले जा रहे दो और व्यापारिक जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत तैयार स्थिति में हैं। सूत्रों के अनुसार, जल्द ही और जहाजों के भी उनके पीछे आने की उम्मीद है।

- ईरान ने 26 जहाजों को गुजरने की दी मंजूरी- गार्ड्स ने सेपाह न्यूज वेबसाइट पर कहा, आज सुबह अमेरिका के भ्रष्ट राष्ट्रपति के इस झूठे दावे के बाद कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है, अलग-अलग देशों के तीन कंटेनर जहाजों को... नौसेना की चेतावनी के बाद वापस भेज दिया गया। हाल ही में ईरान ने कुल 26 जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की मंजूरी दी है। ये जहाज देश के तट के पास स्थित लारक द्वीप के चारों ओर बने एक रास्ते का इस्तेमाल करते हैं।

- ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी की 'चार्जशीट'

भय, भ्रष्टाचार और हिंसा... अमित शाह ने सब बताया

कोलकाता (एजेंसी)।। बंगाल में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार की कथित विफलताओं के खिलाफ चार्जशीट (आरोप पत्र) जारी किया। कोलकाता के न्यूटाउन स्थित एक होटल में संवाददाता सम्मेलन के दौरान शाह ने चार्जशीट जारी करते हुए तृणमूल के 15 वर्षों के शासन में घुसपैठ व महिला अपराधों से लेकर भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और घोटालों के आरोपों की बौछार करते हुए जोरदार हमला बोला। शाह ने कहा कि यह चार्जशीट टीएमसी सरकार के 15 वर्षों के काले कारनामों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। एक प्रकार से आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना है। यह चार्जशीट, टीएमसी सरकार के 15 वर्षों के काले कारनामों का संकलन है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं। विकास के अभाव में बंगाल उद्योग के लिए एक प्रकार से कब्रिस्तान बन चुका है।

पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है बंगाल चुनाव

शाह ने कहा कि बंगाल का ये चुनाव सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ये चार्जशीट बंगाल की जनता द्वारा ममता बनर्जी के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है, जिसको भाजपा एक आवाज दे रही है। भाजपा ने तय किया है कि टीएससी के शासन के खिलाफ जनता के जो मुद्दे हैं इसको आवाज देना और बंगाल के चुनाव में ये जो पूरी अराजकता टीएससी के शासन में फैली है।

टीएमसी ने तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दिया

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में टीएससी ने भय, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दिया है। भाजपा 2011 से इस कुशासन के खिलाफ संघर्ष कर रही है और अब जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी के शासनकाल में उद्योग ठप हो गए हैं और विकास रुक गया है। घुसपैठ, कटमनी और सिंडिकेट राज ने आम लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ा है और 2026 में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। यह चुनाव भयमुक्ति, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए है।

विक्टिम कार्ड की राजनीति करती हैं ममता

शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति खेली है। तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले कभी उनका पैर टूट जाता है, कभी उनके सिर पर पट्टी बंध जाती है, कभी वह बीमार पड़ जाती हैं, और कभी वह चुनाव आयोग के सामने खड़ी होकर बेबसी का नाटक करती हैं और चुनाव आयोग को गालियां देती हैं। लेकिन मैं उन्हें यह बताने आया हूं कि बंगाल के लोग अब विक्टिम कार्ड की इस राजनीति को अच्छी तरह समझ चुके हैं। शाह ने दावा किया कि बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। प्रचंड बहुमत कै साथ बंगाल में भाजपा की सरकार बननी तय है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ यहां तक कहा कि बंगाल में 4 मई को चुनाव नतीजे आएंगे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मोदी युग है यह, पिछड़ गये ट्रंप

(लेखक-बी पी गौतम)

नरेंद्र मोदी की भारत ही नहीं बल्कि, वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता बरकरार है, उन्हें संपूर्ण धरती पर पसंद किया जाता है। लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को पुनः पछाड़ दिया है। भारत को चौथी अर्थ व्यवस्था बनाने का रिकॉर्ड हो या, भाजपा को अजेय बनाने का, वे हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। दुनिया के कई क्षेत्र युद्ध से ग्रस्त हैं, ऐसे भयावह वातावरण में भी अधिकांश देशों के साथ भारत और नरेंद्र मोदी की मित्रता की प्रगाढ़ता में कोई कमी नहीं आई है। अमेरिका, इस्राइल और ईरान युद्ध में फंसे हुये हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पहल के बावजूद आहत ईरान युद्ध रोकने को तैयार नहीं है लेकिन, ईरान का मानना है कि नरेंद्र मोदी शांति बहाल कराने में सक्षम हैं। नरेंद्र मोदी विश्व भर के नेताओं के संपर्क में हैं और उनसे लगातार वार्ता भी कर रहे हैं, इसी विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं बीपी गौतम...

विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 68 प्रतिशत की अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो उन्हें दुनिया के शीर्ष नेताओं में पहले स्थान पर बनाये रखती है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा 2 से 8 मार्च के बीच किये गये सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी अपने वैश्विक समकक्षों से काफी आगे दिखाई दे रहे हैं, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सूची के टॉप-10 में भी स्थान नहीं बना पा सके हैं, उन्हें मात्र 39 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग रहे, जिन्हें 62-62 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग प्राप्त हुई है। सूची में तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः चेक गणराज्य और अर्जेंटीना के नेता रहे, जिन्हें 57 और 56 प्रतिशत की अप्रूवल रेटिंग मिली है, अन्य वैश्विक नेताओं की बात करें तो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर को 24 प्रतिशत और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को मात्र 17 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग मिली है, जिससे वे काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं।

सरकार का नेतृत्व करने का रिकॉर्ड बना

भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, वे देश के सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन गये हैं। रविवार 22 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी कुल मिलाकर 8931 दिन तक अलग-अलग सरकारों के प्रमुख रह चुके हैं, जिससे वे अब भारत के सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन चुके हैं, इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि 8930 दिन तक सिक्किम में सरकार के प्रमुख रहे थे। नरेंद्र मोदी ने 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया था और अब लगातार लगभग 12 वर्षों से प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, इन दोनों को मिला कर वे भारत में किसी भी चुनी हुई सरकार के सबसे लंबे समय तक प्रमुख रहने वाले पहले नेता बन गये हैं लेकिन, मुख्यमंत्री पद की ही बात करें तो, यह रिकॉर्ड अभी भी पवन कुमार चामलिंग (सिक्किम, 24 वर्ष 165 दिन) और नवीन पटनायक (ओडिशा, 24 वर्ष 99 दिन) के नाम पर दर्ज है। नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 12 वर्ष, 227 दिन का रहा था।

मुख्यमंत्री पद पर रिकॉर्ड बनाया

नरेंद्र मोदी ने 7 अक्तूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी, उन्होंने भूकंप के बाद की चुनौतियों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच केशुभाई पटेल का स्थान लिया था, इसके बाद उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतकर गुजरात के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बनाया, साथ ही उनका गुजरात मॉडल देश भर में लोकप्रिय लोकप्रिय हुआ।

भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने का रिकॉर्ड बना

नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी, उनके नेतृत्व में भाजपा ने तीन दशकों में पहली बार पूर्ण बहुमत (282 सीटें) प्राप्त किया, जिससे गठबंधन की राजनीति का युग समाप्त हुआ।

मोदी ने नेहरू की बराबरी की

नरेंद्र मोदी ने 2019 में 303 सीटें जीतकर अपनी स्थिति और मजबूत की। 2024 में भले ही 240 सांसद जीते लेकिन, सत्ता पर पकड़ कमजोर नहीं हुई, आज भी नरेंद्र मोदी सशक्त प्रधानमंत्री हैं, साथ ही जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, जिन्होंने लगातार तीन कार्यकाल प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है।

मोदी ने इंदिरा का रिकॉर्ड तोड़ा

भारत में इंदिरा गांधी 4,077 दिन के साथ लगातार सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही थीं, इस रिकॉर्ड को नरेंद्र मोदी तोड़ चुके हैं। सितंबर 2025 में अपने तीसरे कार्यालय के दौरान नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गये हैं, साथ ही वे पहले गैर-कांग्रेसी नेता हैं, जिन्होंने लगातार दो पूर्ण कार्यकाल पूरे किये हैं।

दुनिया की चौथी अर्थ व्यवस्था बनाया भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में भारत की जीडीपी दोगुनी से भी अधिक 4.5 ट्रिलियन डॉलर के लगभग हो गई है। भारत 2014 की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

भाजपा को बनाया अजेय

भारत के अंदर 2014 में एनडीए गठबंधन सात राज्यों में सत्ता में था लेकिन, 2026 तक 19 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा का शासन स्थापित हो गया, इनमें से 14 राज्यों में सीधी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें हैं।

डिजिटल दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हैं मोदी

नरेंद्र मोदी डिजिटल दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट माने जाते हैं। वर्तमान में एक्स पर उनके 10.6 करोड़, इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ से अधिक और यूट्यूब पर 3 करोड़ से अधिक सब्स क्राइबर्स हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं में से एक बनाते हैं।

अब भी आगे हैं नेहरू और इंदिरा

भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी भी जवाहरलाल नेहरू के नाम है, वे 16 वर्ष 286 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे, उनके बाद इंदिरा गांधी अलग-अलग कार्यकालों को मिलाकर कुल समय 15 वर्ष 350 दिनों तक प्रधानमंत्री रही थीं, यह रिकॉर्ड 2029 के बाद ही टूटना संभव है।

संकट में घिरे गुजरात को उबारा

एक न्यूज एजेंसी के साथ नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के अनुभव को साझा करते हुए कहा था कि 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम शुरू किया तब राज्य कई बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा था। गुजरात भूकंप, चक्रवात, सूखा और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों ने उन्हें और मजबूत बनाया और उन्होंने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने अपनी मां की एक सीख का भी उल्लेख किया था कि गरीबों के लिए काम करना और कभी रिश्वत न लेना, जैसी सीख को उन्होंने अपने जीवन का मार्ग दर्शन बनाया। उनके कार्यकाल में गुजरात ने कृषि, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी तरक्की की और एक मजबूत राज्य के रूप में उभरा। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 में जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तब देश में भरोसे का संकट था लेकिन, जनता ने उन्हें मजबूत समर्थन दिया। नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं और भारत दुनिया की बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं में एक मजबूत देश बनकर उभरा है। पीएम मोदी ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि देश की सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

ट्रंप ने मोदी की प्रशंसा की

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ हमारे शानदार संबंध आगे और भी ज्यादा मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो लोग हैं, जो चीजों को पूरा करते हैं, ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तर पर अहम बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने की जरूरत पर दोनों नेताओं ने गंभीरता से विचार किया, क्योंकि यह वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। अमेरिकी राजदूत की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात और समुद्री सुरक्षा पर फोकस रहा, दोनों नेताओं ने माना कि होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला रहना जरूरी है, ताकि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो।

बातचीत के दौरान भारत ने तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला, सुरक्षित और सुगम बने रहना पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में स्थिरता और शांति के प्रयासों को लेकर संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई।

संपादकीय

सोशल मीडिया पर अंकुश

अमेरिका में लॉस एंजेलिस की एक जूरी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के घातक प्रभावों से त्रस्त एक युवती के पक्ष में सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले से दुनिया भर के अभिवावकों को राहत मिली है। दरअसल, सोशल मीडिया की लत लगाने से जुड़े एक मामले में मेटा और यूट्यूब पर 56 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि एक युवती ने मेटा और यूट्यूब पर आरोप लगाया था कि इनकी वजह से उसे सोशल मीडिया की घातक लत लगी। हालांकि, अब तक ये कंपनियां दलील देती रही हैं कि वे मात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और इसकी सामग्री के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन कोर्ट में वकीलों ने पीड़िता के पक्ष में दलील दी कि जानबूझकर इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ताकि उपयोगकर्ता कथित सोशल मीडिया की लत के शिकार बन जाएं। शुरुआत से पहचान गुप्त रखने वाली बीस वर्षीय युवती केली के वकीलों की दलील को जूरी ने स्वीकार किया कि इस लत से उसकी मानसिक सेहत को नुकसान हुआ है। जूरी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों की दलीलों को दरकिनार करते हुए मेटा और यूट्यूब पर साठ लाख अमेरिकी डॉलर यानी छप्पन करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है। जूरी ने माना कि गूगल तथा मेटा ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के संचालन में अपने मुनाफे के मद्देनजर अनुचित उपायों का सहारा लिया है। जूरी ने इसे अनैतिक भी बताया। जूरी के निर्णय के अनुसार इस मामले में जुर्माने की सत्तर फीसदी राशि मेटा तथा तीस फीसदी रकम गूगल को चुकानी होगी। उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विरुद्ध हजारों मुकदमें चल रहे हैं। जिसमें कई वे लोग भी शामिल हैं जिनके बच्चों ने सोशल मीडिया की लत का शिकार होकर आत्मघाती कदम उठाये हैं। ब्रिटेन समेत कई देशों में अभिभावक इस लत से बच्चों को बचाने के लिये आंदोलन करते रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका में ही विभिन्न अदालतों में सोशल मीडिया के घातक प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिये सैकड़ों मामले चल रहे हैं। विश्वास किया जा रहा है कि इस मुकदमे के फैसले का प्रभाव उन तमाम मामलों में भी पड़ सकता है, जो दुनिया के विभिन्न देशों में चल रहे हैं। हालांकि, दोषी पाये गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कर्ताधर्ता इस फैसले से असहमति जताते हुए इसके खिलाफ अपील करने की बात कर रहे हैं। उनकी दलील है कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव के अनेक अन्य कारण हो सकते हैं, जिसके लिये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यूट्यूब के अधिकारियों का कहना है कि ये सोशल मीडिया साइट नहीं, सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। जबकि पीड़ित युवती के वकीलों की दलील थी कि मेटा आदि कंपनियों ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की संरचना ऐसी बनायी है कि किशोरों को इसकी आदत लग जाए। हकीकत ये है कि भारत समेत दुनिया के करोड़ों किशोर इसकी लत के शिकार बन रहे हैं। यही वजह है हफ्तों चले मुकदमे के दौरान बड़ी संख्या में किशोरों के अभिभावक वादी के पक्ष में अदालत के परिसर में मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि इस फैसले से पहले न्यू मेक्सिको में एक जूरी ने मेटा को इस बात के लिये जवाबदेह ठहराया कि उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वयस्कों की सामग्री तक बच्चों की पहुंच बनी है, जिससे उनके जीवन में यौन अपराधियों का खतरा बढ़ गया है।, भारत समेत कई विकसित व विकासशील देशों में सोशल मीडिया से बच्चों के जीवन में पड़ने वाले घातक प्रभावों को लेकर चिंता सालों से बनी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की मूल भावना

(लेखक-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं)

भारत में धर्म परिवर्तन, अनुसूचित जाति आरक्षण -24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला -संवैधानिक सिद्धांत, न्यायिक व्याख्या और सामाजिक- राजनीतिक प्रभाव का व्यापक विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जड़ें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 अनुच्छेद 25 और कंस्टीटूशन (शेड्यूल्ड क़ास्ट्स) आर्डर,1950 में निहित हैं- कानून में बदलाव, सामाजिक जागरूकता और नीति सुधार जरूरी वैश्विक स्तरपर भारत जैसे बहु- धार्मिक,बहु- सांस्कृतिक और बहु-जातीय समाज में धर्म, जाति और सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का केंद्र रहा है। 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा सुनाया गया ताजा फैसला इसी जटिल विमर्श को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आया है। इस निर्णय में अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि हिंदू,सिख और बौद्ध धर्म को छोड़कर अन्य धर्म विशेषकर ईसाई और इस्लाम अपनाने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा और उससे जुड़े आरक्षण लाभ प्राप्त नहीं होंगे। यह निर्णय केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान की मूल भावना,ऐतिहासिक अन्याय के प्रतिकार और आधुनिक सामाजिक संरचना के बीच संतुलन बनाने का प्रयास भी है। मैं एडवोकेट किशनसनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा कि इस निर्णय की जड़ें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और कंस्टीटूशन (शेड्यूल्ड क़ास्ट्स) आर्डर 1950 में निहित हैं। 1950 के इस आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल उन व्यक्तियों को मिलेगा जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। बाद में इसमें संशोधन कर सिख (1956) और बौद्ध (1990) धर्मों को भी शामिल किया गया, लेकिन ईसाई और मुस्लिम समुदायों को इस दायरे से बाहर रखा गया। अदालत ने अपने ताजा फैसले में इसी संवैधानिक ढांचे को पुनः पुष्ट करते हुए कहा कि धर्मांतरण के साथ ही व्यक्ति का एससी दर्जा तत्काल और पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है।यह फैसला आंध्र प्रदेश से जुड़े एक मामले पर आधारित है, जिसमें चिंथाडा आनंद नामक व्यक्ति जो ईसाई पादरी थे,ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनके साथ जातिगत भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार किया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए एफआईआर रद्द कर दी कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद आनंद का अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो चुका है, इसलिए उन्हें इस कानून के तहत संरक्षण नहीं मिल सकता। इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा, जिससे यह सिद्धांत और अधिक मजबूत हो गया कि धर्म परिवर्तन केवल आस्था का परिवर्तन नहीं, बल्कि कानूनी पहचान में भी बदलाव लाता है।यहां यह समझना आवश्यक है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसमें किसी भी धर्म को मानना,उसका पालन करना और उसका प्रचार करना शामिल है।लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है; इसके साथ कुछ सामाजिक और कानूनी परिणाम भी जुड़े होते हैं।अदालत ने अपने फैसले में इसी संतुलन को रेखांकित करते हुए कहा कि आरक्षण का आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं, बल्कि उस विशेष सामाजिक और धार्मिक ढांचे में झेली गई ऐतिहासिक प्रताड़ना है।चूंकि जाति व्यवस्था मुख्यतः हिंदू सामाजिक संरचना से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए अन्य धर्मों में जाने पर उस विशेष प्रकार की सामाजिक पहचान स्वतः समाप्त हो जाती है। साथियों बात अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक ढांचा इसको समझने की करें तो भारत में अनुसूचित जातियों की अवधारणा का मूल उद्देश्य उन समुदायों को विशेष संरक्षण देना था, जिन्होंने सदियों तक सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना किया। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश,1950 इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस आदेश के अनुसार, प्रारंभ में केवल हिंदू धर्म के भीतर आने वाले दलित समुदायों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था। बाद में 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी इसमें शामिल किया गया।संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे किन समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करेंगे।वहीं अनुच्छेद 25प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है। यही वह बिंदु है जहां अधिकारों का टकराव उत्पन्न होता है एक ओर धर्म बदलने की स्वतंत्रता,दूसरी ओर सामाजिक न्याय की जबरदस्त सटीक नीतियां। साथियों बात अगर हम इस मुद्दे को अपने आप में लंबे समय से विवादों से घिरा हुआ है इसको समझने की करें तो, कई समाज शास्त्रियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि जातिगत भेदभाव केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचना में गहराई तक व्याप्त है। उदाहरण के लिए,भारत में ईसाई और मुस्लिम समुदायों के भीतर भी दलित ईसाई और पसमांदा मुस्लिम जैसी पहचानें मौजूद हैं, जो यह दर्शाती हैं कि धर्म परिवर्तन के बावजूद सामाजिक भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होता। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या केवल धर्म के आधार पर आरक्षण से वंचित करना वास्तव में सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है?इस बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू पुनः धर्मांतरण से जुड़ा है।अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म छोड़कर पुनः हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म अपनाता है, तो वह पुनः अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकता है—बशर्ते वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सामुदायिक स्वीकृति। यानी, व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसका मूल संबंध उसी जाति से है और उसका समुदाय उसे पुनः स्वीकार करता है। यह शर्त अपने आप में सामाजिक जटिलताओं को जन्म देती है, क्योंकि यह व्यक्तिगत पहचान को सामुदायिक मान्यता पर निर्भर बनाती है। साथियों बात अगर हम 24 मार्च 2026 का निर्णय- कानूनी स्पष्टता या सामाजिक विवाद? इसको समझने की करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म परिवर्तन के साथ ही एससी का दर्जा समाप्त हो जाएगा। अदालत ने कहा कि 1950 का आदेश पूरी तरह स्पष्ट है और इसमें जिन धर्मों का उल्लेख नहीं है, उनमें जाने पर व्यक्ति एससी की श्रेणी से बाहर हो जाता है।

इसका अर्थ यह है कि यदि कोई दलित ईसाई या मुस्लिम बनता है, तो वह एससी आरक्षण और एससी /एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का लाभ नहीं उठा सकता।यह निर्णय कानूनी रूप से स्पष्टता प्रदान करता है,लेकिन सामाजिक दृष्टि से यह कई प्रश्न भी खड़े करता है।

साथियों बात अगर हम इस निर्णय के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को समझने की करें तो ये व्यापक हो सकते हैं। यदि भविष्य में नीति में बदलाव कर ईसाई और मुस्लिम दलितों को भी एससी आरक्षण में शामिल किया जाता है, तो इससे आरक्षण की वर्तमान संरचना पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे मौजूदा लाभार्थियों के हिस्से में कमी आ सकती है।इसके अलावा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरक्षित सीटों पर नए समुदायों की भागीदारी बढ़ेगी। यह परिवर्तन भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है।

दूर करें अध्यात्म विद्या का अभाव

चिंतन मनन

अध्यात्म विद्या के विषय में अधिकांश भौतिक विद्वान शिक्षा को ही विद्या मान बैठते हैं। वे विद्या और शिक्षा के अंतर को भी समझने में असमर्थ हैं जबकि विद्या और शिक्षा में धरती और आसमान का अंतर है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए महात्मा परमचेतनानंद ने अपने प्रवचन में कहा कि शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना। भौतिक शिक्षा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है जिसका संबंध ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों व मन बुद्धि तक सीमित है। इसके अतिरिक्त विद्या शब्द विद् धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना अर्थात् वास्तविक ज्ञान।

यह ज्ञान स्वयं अंदर से प्रकट होता है, इसे ही अध्यात्म ज्ञान कहा जाता है। इसे आत्मा की गहराई में पहुंचने पर ही जाना जाता है। शिक्षा के विद्वान अहंकार से ग्रसित होते हैं, उनमें विनम्रता का अभाव होता है जबकि विद्या का प्रथम गुण विनम्रता है। विद्या वास्तव में मानव की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है।

इस अध्यात्म विद्या से मानव निष्काम कर्म योगी बनता है जो सभी को समान भाव से देखता है। पहले निष्काम कर्म योगी को ही प्रजा अपना राजा चुनती थी। वे अपने पुत्र तथा अन्य प्रजा के साथ समान रूप से न्याय करते थे। आज के असमय में अध्यात्म विद्या का अभाव होने के कारण राजा और प्रजा दोनों ही अशांत हैं फिर भी इसे ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि अध्यात्म विद्या के वेत्ता तत्वदर्शी संत आज भी मौजूद हैं।

विचार मंथन

ट्रंप के पागलपन पर भड़के रिपब्लिकन सांसद

(लेखक - -सनत जैन)

अमेरिका में ट्रंप का बढ़ता विरोध

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अलग-थलग पडते चले जा रहे हैं। उन्होंने बिना संसद की अनुमति लिए ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अभी तक वह इस हमले का कोई कारण अमेरिका की संसद को नहीं बता पा रहे हैं। इस युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के खर्चे के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की है। इतनी बड़ी राशि उन्हें क्यों चाहिए है, वह संसद को नहीं बता पा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों को ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। उसमें वह अपने ही सांसदों की बातों का जवाब नहीं दे पाए। जिसके कारण सांसदों ने बैठक के दौरान ही अपनी नाराजी जाहिर की। कुछ सांसद गुस्से में बैठक से बाहर निकल आए, उन्होंने ट्रंप के प्रति अपनी नाराजी सार्वजनिक रूप से जिस तरह जाहिर की है, उससे ऐसा लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का विरोध रिपब्लिकन पार्टी में भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने उन्हें पागल बताते हुए उनके बयानों की बड़ी आलोचना की। जिस तरह के मनमाने वह निर्णय ले रहे हैं, उसका अब रिपब्लिकन सांसद भी विरोध कर रहे हैं। सांसदों का कहना था, कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध नहीं लड़ने की घोषणा के साथ राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। शांति स्थापित करना चाहते थे। अब खुद ही युद्ध में अमेरिका को झोंक दिया है। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। निम्न एवं मध्यम वर्ग में ट्रंप को लेकर नाराजी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। बढ़ते खर्च के कारण अमेरिका की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका का राजस्व पूर्व के वर्षों की तुलना में कम हो रहा है। युद्ध में लगातार जिस तरह से खर्च हो रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नई-नई मांग कर रहे हैं। इसको लेकर रिपब्लिकन सांसद भी नाराज हैं।

टैरिफ को लेकर भी उन्होंने नाटो और अमेरिका के मित्र देशों के साथ-साथ सारी दुनिया के बड़े-बड़े देशों को नाराज कर अमेरिका के खिलाफ एकजुट कर दिया है। ईरान से युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने नाटो और मित्र देशों को धमकाया है। उसके कारण अमेरिका बिल्कुल अलग-थलग पड गया है। इजराइल के साथ मिलकर ईरान से जो युद्ध शुरू किया है वह अमेरिका के लिए भारी साबित हो रहा है। खाड़ी के जिन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, ईरान ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए उन अड्डों और वहां के सैन्य संसाधनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अमेरिका के जंगी जहाज और सबसे ताकतवर विमानो को ईरान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका के सैन्य हथियारों को इसके पहले कभी इस तरह की चुनौती नहीं मिली थी, जो अब मिल रही है। ऐसी तबाही इसके पहले अमेरिका की कभी नहीं हुई ,जो पिछले एक माह में देखने को मिली है। इसके कारण अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नाराजी बढ़ती चली जा रही है। आम जनता और डेमोक्रेटिक पहले से ही ट्रंप से नाराज हैं। अब रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी ट्रंप से नाराज हो गए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता मात्र 36 फीसदी रह गई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए लग रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से लड़ते-लड़ते अन्य कई देशों के निशाने पर भी आ गए हैं। उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका में अपनों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। ट्रंप जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उन बयानों को देखते हुए अब सारी दुनिया उन्हें साइको अथवा पागल की तरह देख रही है। अमेरिका का सर्वोच्च कमांडर युद्ध के दौरान इस तरह की हरकत करेगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। ट्रंप के पागलपन और अहंकार का खामियाजा पूरे अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों से सारी दुनियां के देशों में आर्थिक संकट के साथ ही गैस और तेल का संकट उठ खड़ा हुआ है। सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे अधिकांश देशों के लोग परेशान है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जाने लगा है जो हालात सोवियत रूस के विघटन के समय थी वही स्थिति आज अमेरिका में देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि अमेरिका की संसद कैसे डोनाल्ड ट्रंप को नियंत्रित करती है। डोनाल्ड ट्रंप के रहते क्या एक नया इतिहास अमेरिका लिखने जा रहा है। इसकी चर्चा सारी दुनिया में हो रही है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रुपया रिकॉर्ड गिरावट पर, विदेशी भंडार का पहरा आरबीआई संभालेगा

विदेशी दबाव और निवेशक आउटफ्लो के चलते आरबीआई का आर्थिक संतुलन चुनौतीपूर्ण

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस समय ऐतिहासिक चुनौती का सामना कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध, वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी निवेशकों के अचानक अरबों डॉलर की निकासी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। रुपये की गिरावट रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है, वहीं विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना भी अनिवार्य हो गया है। आम आदमी की जेब, उद्योग और सरकार–सब इस अस्थिरता से सीधे प्रभावित हैं। आरबीआई के सामने दो विकल्प हैं- या तो रुपये को स्थिर रखें, जिससे घरेलू नकदी और ब्याज दरों पर असर पड़ेगा, या विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करें, जिससे रुपये में गिरावट आ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में आरबीआई शायद रुपये की कुछ कमजोरी सहन करके विदेशी मुद्रा भंडार को प्राथमिकता देगा, ताकि लंबी अवधि में देश की आर्थिक स्थिरता सुरक्षित रह सके। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध और वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अप्रत्याशित दबाव डाला है। विदेशी निवेशकों ने मार्च में 12.1 अरब डॉलर निकाल लिए, जो एक महीने में अब तक का सबसे बड़ा आउटफ्लो है। इस वजह से रुपये की गिरावट 74 के स्तर तक पहुंच गई, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को विदेशी मुद्रा भंडार और रुपये की स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया है। भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार 13 मार्च तक 710 अरब डॉलर था, जिसमें मुख्य रूप से विदेशी मुद्राएं, सोना, विशेष निकासी सुविधा (एसडीआर) और आईएमएफ में विशेष ट्रेंच पोजिशन शामिल हैं। सोना लगभग कभी बेचा नहीं गया और एसडीआर या ट्रेंच पोजिशन की सीमा सीमित है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक तौर पर आरबीआई के पास विदेशी मुद्राओं का मुख्य भंडार ही इस्तेमाल करने योग्य है। आरबीआई के पास रुपये की गिरावट को रोकने के दो विकल्प हैं। पहला, हाजिर बाजार में विदेशी मुद्रा बेचकर रुपये को खरीदना, जिससे रुपये की कीमत स्थिर हो सकती है लेकिन घरेलू नकदी कम हो जाएगी और ब्याज दरों में वृद्धि का खतरा बढ़ेगा। दूसरा, फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट में मुद्रा बेचना, जिससे रुपये की गिरावट रोकी जा सकती है और ब्याज दरों पर असर नहीं पड़ेगा। जनवरी से अब तक आरबीआई ने लगभग 68 अरब डॉलर फॉरवर्ड मार्केट में बेचे, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 500 अरब डॉलर तक घट गया। हालांकि रुपये की गिरावट आम आदमी और उद्योग दोनों पर असर डालती है, लेकिन वर्तमान वैश्विक अस्थिरता और उच्च आयात बिल के दबाव में आरबीआई के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखना अहम हो गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि रुपये की गिरावट अभी 97 तक जा सकती है। इसलिए, आरबीआई संभवतः रुपये की कुछ गिरावट सहन कर विदेशी मुद्रा भंडार को प्राथमिकता देगा। इस स्थिति में रुपये में गिरावट का सीधा असर आम आदमी की जेब पर दिखाई देगा। ईंधन, आयातित वस्तुएं और महंगाई बढ़ सकती है। वहीं यदि आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा में सफल रहता है, तो देश लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय भुगतान और आयात बिल की जरूरतों को पूरा कर सकेगा।

लंबी ट्रिप के लिए सुरक्षित और आरामदायक हैं ये 5 दमदार एसयूवी

नई दिल्ली ।

लंबी दूरी और अनजान रास्तों पर भरोसेमंद गाड़ी होना सबसे जरूरी होता है। होंडा एलीवेट अपनी मजबूत इंजीनियरिंग और भरोसेमंद 1.5-लीटर आई-वीटेक पेट्रोल इंजन के लिए जानी जाती है। इसकी केबिन आरामदायक और ड्राइव स्मूथ है, जिससे लंबी दूरी का सफर आसान हो जाता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर फुल-साइज एसयूवी में 2.8-लीटर डीजल इंजन और 4×4 विकल्प है, जो दुर्गम रास्तों और कीचड़ वाले इलाके में भी बेहतरीन प्रदर्शन देती है। इसुजु एमयू-एक्स में 1.9-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन है। इसकी मजबूती इसे कठिन रास्तों के लिए आदर्श बनाती है। 4गुणा 2 और 4गुणा4 विकल्प लंबी ट्रिप में सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं।

ईंधन बचाने वाली 5 पेट्रोल-हाइब्रिड कारें बाजार में उपलब्ध

नई दिल्ली ।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब बाजार में पेट्रोल-हाइब्रिड कारें आ चुकी हैं, जो माइलेज के मामले में डीजल को भी टक्कर देती हैं। इनमें पेट्रोल इंजन के साथ स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो ईंधन की बचत करती है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस इस लिस्ट में सबसे आगे है। यह कार एक लीटर पेट्रोल में 28.6 किमी तक चलती है। 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन लंबी ट्रिप के लिए इको, नॉर्मल और पावर तीन ड्राइविंग मोड देता है। होंडा सिटी हाइब्रिड 1.5-लीटर इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटरों से 125बीएचपी पावर देती है और 26.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है। इसमें लेन वॉच असिस्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स सुरक्षा में मदद करते हैं। बड़ी फैमिली के लिए टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड 23.24 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है। इसका 2.0-लीटर इंजन फैमिली और सामान के साथ भी हाईवे पर दमदार प्रदर्शन करता है। इसमें जेबीएल साउंड सिस्टम और बड़ी सनरूफ जैसी लग्जरी सुविधाएं दी गई हैं। टोयोटा कैमरी 2.5-लीटर इंजन के बावजूद 25.49 किमी प्रति लीटर

का माइलेज देती है। इसका इंटीरियर लग्जरी और आरामदायक है, जिसमें सीटें रीक्लाइन करने योग्य हैं। वोल्वो एक्ससी90 अपनी सेफ्टी और रुतबे के लिए लोकप्रिय है। 2.0-लीटर इंजन और 48वी सिस्टम ईंधन बचाने में मदद करता है। इसमें लग्जरी लेदर सीट्स और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स लंबे सफर को सुरक्षित बनाते हैं।

ये पांच पेट्रोल-हाइब्रिड कारें अब हाईवे ट्रिप के लिए बेहतरीन विकल्प बन गई हैं।

ईंधन बचाने वाली 5 पेट्रोल-हाइब्रिड कारें बाजार में उपलब्ध

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब बाजार में पेट्रोल-हाइब्रिड कारें आ चुकी हैं, जो माइलेज के मामले में डीजल को भी टक्कर देती हैं। इनमें पेट्रोल इंजन के साथ स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो ईंधन की बचत करती है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस इस लिस्ट में सबसे आगे है। यह कार एक लीटर पेट्रोल में 28.6 किमी तक चलती है। 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन लंबी ट्रिप के लिए इको, नॉर्मल और पावर तीन ड्राइविंग मोड देता है। होंडा सिटी हाइब्रिड 1.5-लीटर इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटरों से 125बीएचपी पावर देती है और 26.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है। इसमें लेन वॉच असिस्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स सुरक्षा में मदद करते हैं। बड़ी फैमिली के लिए टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड 23.24 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है। इसका 2.0-लीटर इंजन फैमिली और सामान के साथ भी हाईवे पर दमदार प्रदर्शन करता है। इसमें जेबीएल साउंड सिस्टम और बड़ी सनरूफ जैसी लग्जरी सुविधाएं दी गई हैं। टोयोटा कैमरी 2.5-लीटर इंजन के बावजूद 25.49 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है। इसका इंटीरियर लग्जरी और आरामदायक है, जिसमें सीटें रीक्लाइन करने योग्य हैं। वोल्वो एक्ससी90 अपनी सेफ्टी और रुतबे के लिए लोकप्रिय है। 2.0-लीटर इंजन और 48वी सिस्टम ईंधन बचाने में मदद करता है।

जेवर एयरपोर्ट से यमुना एक्सप्रेस-वे के आसपास जमीन के दाम बढ़ने की उम्मीद

एसईजेड के कुछ सेक्टरों में दरें पहले ही करीब 8,000 रुपए प्रति वर्ग फुट पहुंची

नोएडा, ।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन से यमुना एक्सप्रेस-वे के आसपास जमीन के दाम बढ़ने के आसार हैं। बाजार विश्लेषकों और डेवलपरों का कहना है कि रिहायशी और औद्योगिक दोनों इकाइयों की कीमतों में इजाफा होगा जिसका असर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाजारों पर भी पड़ेगा। रियल एस्टेट सलाहकार फर्म कॉलियर्स के आंकड़ों के मुताबिक यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में अगले दो सालों में भूखंड के दाम करीब 28 फीसदी और अपार्टमेंट की कीमतें करीब 22 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। जेवर भी इसी इलाके में स्थित है जहां नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आज यानी शनिवार को होना है।रिपोर्ट के मुताबिक जेवर हवाई अड्डे की घोषणा 2021 में की गई थी। उसके बाद से ही इस क्षेत्र के रियल एस्टेट में काफी हलचल रही है। पिछले पांच सालों में यीडा इलाके के अपार्टमेंट की कीमतें करीब तीन गुना बढ़ चुकी हैं। कीमतें 2020 में 3200 रुपए प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 2025 में 9,600 रुपए प्रति वर्ग फुट दर्ज की गईं। नैशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरेडको) के अध्यक्ष ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस-वे एसईजेड के कुछ सेक्टरों में दरें पहले ही करीब 8,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह काफी अहम है। खास तौर पर यह देखते हुए कि जेवर के प्रभाव वाले इलाकों जमीन के दाम पिछले पांच सालों में करीब 40 फीसदी बढ़ चुके हैं।

पेट्रोल, डीजल की कीमतों को बढ़ने से रोकने सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी

अगले वित्त वर्ष में सरकार का राजस्व 1.3 लाख करोड़ रुपए हो सकता है कम

नई दिल्ली,। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की भारी कटौती की है। पेट्रोल, डीजल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है ताकि उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़े लेकिन इससे अगले वित्त वर्ष में सरकार का राजस्व करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए कम हो सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है और डीजल पर यह 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया है। कटौती तुरंत लागू हो गई है। सरकार ने पिछले साल अप्रैल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया था। सरकार ने देसी बाजार में दोनों की पर्याप्त उपलब्धता तय करने के लिए डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एक बार फिर शुल्क लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीजल निर्यात पर 21.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ निर्यात पर 29.5 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया है। पहले इनके निर्यात पर शुल्क नहीं था। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच भारत से 1.4 करोड़ टन पेट्रोल और 2.36 करोड़ टन डीजल का निर्यात किया, जिसमें बड़ा हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज का रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में प्रति लीटर 10 रुपए की कमी की गई है। इससे उपभोक्ता कीमत में इजाफे से बच जाएंगे।सरकार के अधिकारियों का अनुमान है कि शुल्क में कटौती से अगले पंद्रह दिनों में करीब 7,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इससे संकेत मिलता है शुल्क में यह कटौती कुछ समय के लिए ही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन ने कहा कि सरकार हर पंद्रह दिनों में डीजल और एटीएफ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की समीक्षा करेगी। पेट्रोल की कीमतें रोजाना बदलने वाली मूल्य व्यवस्था से तय की जाती हैं, जो कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत, विनिमय दर और करों के पिछले 15 दिन के औसत पर काम करती है। अंतिम उपभोक्ता मूल्य में आधार मूल्य, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, डीलर कमीशन और राज्य-स्तरीय वैट शामिल होता है।उन्होंने कहा कि शुल्क कटौती से अगले 15 दिन में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी तेल कंपनियों को करीब 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि कटौती पूरे वित्त वर्ष 2027 में लागू रही तो सरकारी खजाने को 1.3 लाख करोड़ से 1.7 लाख करोड़ रुपए तक की चपत लग सकती है। एक अन्य अर्थशास्त्री ने कहा कि शुल्क में कटौती से तेल कंपनियों को राहत मिलेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो कीमतों में वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता था।

भारत के लिए ईरानी कच्चे तेल की आपूर्ति सीमित, चीन बन रहा प्राथमिक खरीदार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति- ईरान के पास अंतरराष्ट्रीय बिक्री के लिए अतिरिक्त तेल उपलब्ध नहीं

नई दिल्ली।

भारतीय रिफाइनरियों के लिए ईरानी कच्चा तेल अब उपलब्ध तो है, लेकिन मात्रा बेहद सीमित और समय-सीमा बहुत संकीर्ण है। वॉशिंगटन द्वारा फ्लोटिंग स्टोरेज और ट्रांजिट में मौजूद ईरानी तेल की बिक्री के लिए हालिया छूट देने के बाद इसका रुख बदल गया है, और अधिकांश तेल चीन की ओर जा रहा है। भारत मार्च और अप्रैल में डिलीवरी के लिए रूस से स्टोरेज में मौजूद 100 मिलियन बैरल तेल का 60 फीसदी पहले ही खरीद चुका है, जबकि ईरानी तेल के लिए भारत के हिस्से में 10 मिलियन बैरल से कम मिल सकते हैं। एक वरिष्ठ ट्रेडर ने बताया कि डिलीवरी के लिए केवलएक महीने की सीमित समय-सीमा (19 अप्रैल तक) ने भारतीय सरकारी रिफाइनरियों के लिए सप्लाई चेन प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इस समय में विक्रेताओं की पहचान, उनकी विश्वसनीयता की जांच और शिपिंग व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है। पहले ईरानी कच्चे तेल की बिक्री पूरी तरह नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी (एनआईओसी) के नियंत्रण में थी। लेकिन अब यह बिक्री मुख्य रूप से उन ट्रेडर्स के नियंत्रण में है, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) से जुड़े हैं। ब्रिटेन स्थित एनर्जी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंधित तेल की आपूर्ति अब संदिग्ध हितों द्वारा की जा रही है, जिनके पास फ्लीट कंपनियों और किराये पर लिए गए जहाजों का नेटवर्क है। एक सीनियर रिफाइनिंग अधिकारी ने कहा कि इस नई व्यवस्था में तेल खरीदना और डिलीवरी सुनिश्चित करना भारतीय रिफाइनरियों के लिए और कठिन हो गया है। मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ईरान के पास अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए अतिरिक्त तेल उपलब्ध नहीं है। अमेरिकी वित्त मंत्री की हालिया टिप्पणियां मुख्य रूप से खरीदारों को आश्वस्त करने और बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से प्रतीत होती हैं। कई वर्षों से ईरानी तेल का खुले तौर पर व्यापार नहीं हुआ है, जिससे इसकी गुणवत्ता और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। भारतीय रिफाइनर-सरकारी

या निजी ईरानी तेल खरीदने के इच्छुक थे, खासकर तब जब अमेरिका ने 20 मार्च को स्टोरेज और ट्रांजिट में मौजूद तेल पर 30 दिन की छूट दी। लेकिन सीमित समय-सीमा, सप्लाई की कमी और आईआरजीसी से जुड़े नेटवर्क के कारण इस दिशा में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। इस स्थिति में भारत के लिए मुख्य तेल स्रोत अभी भी रूस और अन्य पारंपरिक आपूर्तिकर्ता हैं। ईरानी तेल संभावित स्रोत के रूप में मौजूद है, लेकिन मात्रा कम और जोखिम अधिक है।

नए फोन रियलमी 16 5जी जल्द होगा लॉन्च

नई दिल्ली । चायनीज कंपनी रियलमली जल्द ही अपने नए फोन रियलमी 16 5जी को लॉन्च करने जा रही है, जिसमें भारत का पहला सेल्फी मिरर फीचर दिया गया है। इसे ÷सेल्फी मिरर फोन÷ के नाम से टीज किया गया है। अब यूजर पीछे वाले कैमरे से भी आसानी से शानदार सेल्फी ले सकेंगे। फोन के रियर कैमरा मॉड्यूल के साथ एक छोटा मिरर जुड़ा होगा, जिससे खुद को देखकर हाई क्वालिटी फोटो क्लिक की जा सकेगी। रियलमी 16 5जी का डिजाइन भी यूनिक और प्रीमियम बताया जा रहा है। पीछे की तरफ लंबा कैमरा बार दिया गया है, जो पिक्सल और आईफोन जैसी याद दिलाता है। कंपनी इसे ÷एयर डिजाइन÷ कह रही है, यानी फोन हल्का और पकड़ने में आरामदायक रहेगा। कलर चेंजिंग फिनिश इसे और स्टाइलिश बनाती है। फोन के कैमरा सेटअप पर खास फोकस है। इसमें 50एमपी का सोनी आईएमएक्स 852 मेन कैमरा और 2एमपी सेकेंडरी सेंसर दिए जाने की संभावना है। साथ ही 50एमपी का फ्रंट कैमरा भी मिलेगा। सेल्फी मिरर फीचर के साथ यह सेटअप यूजर्स को नया डिजिटल अनुभव देगा। परफॉर्मेंस के लिए फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 टर्बो प्रोसेसर का इस्तेमाल हो सकता है।

औद्योगिक सेक्टर के लिए राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन का कोटा बढ़ा

सरकार ने 20 फीसदी की वृद्धि कीश् अब यह कोटा 70 फीसदी हो गया

नई दिल्ली,।

केंद्र सरकार ने इस्पात और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों समेत तमाम औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन में 20 फीसदी की और वृद्धि की है। इससे अब यह कोटा युद्ध से पहले की मांग का 70 फीसदी हो गया है।पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि अतिरिक्त आपूर्ति इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, डाई, रसायन और प्लास्टिक जैसे श्रम वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इनसे ही अन्य कई जरुरत क्षेत्र जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा 50 फीसदी आवंटन के अतिरिक्त अब 20 फीसदी और गैस दी जाएगी, जिससे कुल वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन गैर-घरेलू एलपीजी के युद्ध से पहले की मांग का 70 फीसदी हो जाएगा। तेल मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में तीन अलग-अलग निर्देशों के जरिए राज्यों को युद्ध-पूर्व वाणिज्यिक एलपीजी कोटे का 40 फीसदी आवंटित किया था।

मंत्रालय ने पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुधारों के आधार पर राज्यों को 10 फीसदी अतिरिक्त एलपीजी आवंटित की थी।

अब ताजा फैसले के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त 20 फीसदी एलपीजी प्राथमिकता वाले उद्योगों को दी जाएगी। इनमें, प्रक्रिया उद्योगों या उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें विशेष ताप उद्देश्यों के लिए एलपीजी की जरुरत होती है, क्योंकि इसके विकल्प के तौर पर कोई और गैस इस्तेमाल नहीं की जा सकती।

बाजार में जल्द एंट्री करेंगे आईईआईटी फोक्स्ड म्युचुअल फंड

एनएसई के डेडिकेटेड इंडेक्स लॉन्च से बढ़ी उम्मीद

नई दिल्ली,। इस महीने की शुरुआत में एनएसई के निफ्टी आईईआईटी और रियल्टी इंडेक्स के लॉन्च के साथ ही भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईईआईटी) पर फोक्स्ड पहले म्युचुअल फंड स्कीम्स का रास्ता साफ हो गया है। कई फंड हाउस इस बेंचमार्क से जुड़े पैसिव प्रोडक्ट्स लाने पर विचार कर रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसी पहली योजनाएं 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च होंगी, जब नियम फंड हाउस को आईईआईटी-आधारित प्रोडक्ट पेश करने की अनुमति देंगे।एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि वे नए लॉन्च किए गए इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले पैसिव फंड्स पर विचार कर रहे हैं। नवी एएमसी के सीईओ आदित्य मुल्की ने कहा कि हम अभी किसी तत्काल फाइलिंग पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इस इंडेक्स का गहराई से मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि यह रिटेल निवेशकों के लिए एसेट एलोकेशन के विकल्प बढ़ाने के हमारे उद्देश्य के अनुरूप है। डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में पैसिव इन्वेस्टमेंट्स और प्रोडक्ट्स के हेड अनिल घेलानी ने कहा कि उनका फंड हाउस भी इस इंडेक्स का अध्ययन कर रहा है।यह कदम सेबी के उस फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें जनवरी 2026 में आईईआईटी को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया। इससे 1 जुलाई से इन्हें इक्विटी इंडेक्स में शामिल करने की अनुमति मिल गई। पहले आईईआईटी को हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट माना जाता था, जिसके कारण इक्विटी स्कीम्स में उनकी हिस्सेदारी सीमित थी और एक्टिव फंड्स में इनका एक्सपोजर 10 फीसदी तक ही सीमित रखा जाता था। इस पुनर्वर्गीकरण और इंडेक्स में शामिल किए जाने से आईईआईटी में लिक्विडिटी बढ़ने, उनकी विजिबिलिटी मजबूत होने और म्युचुअल फंड्स की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। निफ्टी आईईआईटी और रियल्टी इंडेक्स में आईईआईटी और रियल एस्टेट कंपनियों का मिक्स शामिल है। इसमें लिस्टेड पांच आईईआईटी का करीब 64 फीसदी हिस्सा है, जबकि बाकी हिस्सा रियल्टी स्टॉक्स का है, जिनमें डीएलएफ और फोनिक्स मिल्स जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। यह 15 शेयरों वाला इंडेक्स फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर वेटेड है और किसी भी एक कंपनी का वेट 15 फीसदी से ज्यादा नहीं रखा गया है। पिछले एक साल में इसने 12.4 फीसदी का रिटर्न दिया है और करीब 3.3 फीसदी का डिविडेंड यील्ड भी प्रदान करता है।

ओएमओ से 3.5 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड की खरीद से घटेगा ट्रेजरी घाटा

स्विच ऑक्शन से भी बैंकों को मदद मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली,। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस तिमाही में अब तक खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के जरिये 3.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड की भारी भरकम खरीदारी से बैंकों के ट्रेजरी कारोबार से जुड़ा घाटा कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा स्विच ऑक्शन से भी बैंकों को मदद मिलने की उम्मीद है। बॉन्ड यील्ड में उछाल बैंकों के ट्रेजरी कारोबार पर असर हुआ है। 10 साल की अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों पर यील्ड जनवरी से अब तक 35 आधार बढ़ चुकी है। अकेले मार्च में इसमें 28 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई। चालू तिमाही में 5 साल की अवधि के सरकारी बॉन्ड और 15 साल की अवधि के बॉन्ड पर यील्ड क्रमशः 34 आधार अंक और 32 आधार अंक तक बढ़ गई है।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों और कुछ बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों को अभी भी कुछ मार्क-टू-मार्केट नुकसान का सामना करना पड़ सकता है लेकिन जिन बैंकों ने ओएमओ खरीद या स्विच ऑपरेशन में भाग लिया है वे इसे कम करने की बेहतर स्थिति में होंगे। एक बॉन्ड कारोबारी ने कहा कि नुकसान तो होगा ही क्योंकि मौजूदा यील्ड 2022 में देखे गए उच्चतम स्तर के करीब हैं जब आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा रहा था, उनमें अधिकांश अब घाटे में होंगे। अधिकारी ने कहा कि अगर बैंकों ने आरबीआई द्वारा बॉन्ड खरीदने के दौरान मुनाफा कमाया होता तो शुद्ध आधार पर वे अभी भी घाटे में हो सकते थे लेकिन नुकसान कम किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि प्रभावी रूप से मार्क-टू-मार्केट नुकसान का एक बड़ा हिस्सा आरबीआई द्वारा वहन किया गया है। अगर ये ओएमओ नहीं हुए होते तो आज बाजार में भारी नुकसान होता। शुक्रवार को 10 साल की सरकारी बॉन्ड की यील्ड 6.94 फीसदी पर पहुंच गई। पिछले साल मार्च के अंत में 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड 6.58 फीसदी थी। जानकारों का कहना है कि आरबीआई की तरफ से बॉन्ड खरीदारी ने नुकसान कम करने में अहम भूमिका निभाई है। अनुमान है कि केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष में करीब 9 लाख करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड खरीदे हैं जिन पर यील्ड मौजूदा स्तरों से करीब 25 आधार अंक कम है। एक बॉन्ड कारोबारी ने कहा कि हाल में यील्ड में आई उछाल को देखते हुए कुछ बैंक खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और कुछ बड़े निजी बैंक इस तिमाही में बॉन्ड कारोबार में नुकसान उठा सकते हैं।

बाजार में पावरफुल और मजेदार टर्बो पेट्रोल एसयूवी के विकल्प मौजूद

नई दिल्ली।

यदि आप कम बजट में दमदार एसयूवी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो बाजार में आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं। इन गाड़ियों में टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कम इंजन क्षमता के बावजूद बेहतर पावर और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। इस लिस्ट में टाटा मोटर्स, किआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा के मॉडल के साथ-साथ नई रिनॉल्ट डस्टर भी शामिल है, जो एक बार फिर चर्चा में है। आज के ग्राहक सिर्फ माइलेज पर नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और ड्राइविंग अनुभव पर भी ध्यान देते हैं। टर्बो पेट्रोल इंजन वाली एसयूवी शहर और हाईवे दोनों पर मजेदार और रेस्पॉन्सिव ड्राइव देती हैं। स्कोडा कियाक कम बजट में एक शानदार विकल्प है। यह एमक्यूबी एओ इन प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है और इसमें 1.0 लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 118एचपी पावर और 178एनएम टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैन्युअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ऑप्शन उपलब्ध हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी यह मजबूत है और इसे भारत एनकैप में 5-स्टार रेटिंग मिली है। कीमत लगभग 7.59 लाख से 12.99 लाख रुपये के बीच है। किआ सोनेट फीचर्स और परफॉर्मेंस का बेहतरीन बैलेंस देती है। इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 118एचपी और 172एनएम टॉर्क जनरेट करता है। आईएमटी और डीसीटी ऑटोमैटिक जैसे एडवांस ट्रांसमिशन विकल्प इसमें उपलब्ध हैं। आरामदायक सस्पेंशन और अलग-अलग वेरिएंट्स इसे 15 लाख रुपये से कम बजट में आकर्षक बनाते हैं। नई रिनॉल्ट

डस्टर भारतीय बाजार में एक बार फिर वापसी कर रही है। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प और नया डिजाइन मिलेगा, जो इसे मौजूदा सेगमेंट में मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एमआई विरुद्ध केकेआर : वानखेड़े में हाईवोल्टेज टक्कर

– आंकड़ों में मुंबई भारी लेकिन हालिया फॉर्म में कोलकाता आगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत के साथ ही रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला है। टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने की उम्मीद है, जहां मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट रायडर आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला 29 मार्च को मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी।

मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पाण्डया के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइटराइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे संभाल रहे हैं। दोनों कप्तानों के लिए यह मुकाबला खास होगा, क्योंकि शुरुआती जीत टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे सकती है। अगर दोनों टीमों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहां मुंबई इंडियंस का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। अब तक दोनों के बीच कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें मुंबई ने 24 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता को सिर्फ 11 मैचों में जीत मिली है। शुरुआती सीजन में मुंबई ने लगातार दबदबा बनाए रखा और 2008-09 में सभी मुकाबले अपने नाम किए।

हालांकि, 2012 के बाद तस्वीर थोड़ी बदली। 2014 और 2015 में केकेआर ने मुंबई पर बढ़त बनाई और चार में से तीन मैच जीते। इसके बाद 2016 से 2018 तक मुंबई ने फिर से पूरी तरह वापसी करते हुए लगातार सात मुकाबले जीत लिए। लेकिन हालिया सीजनों पर नजर डालें तो कोलकाता ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले चार सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए छह मुकाबलों में से चार में केकेआर ने जीत दर्ज की है, जो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। खिताब की बात करें तो मुंबई इंडियंस अब तक पांच बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है और छठे खिताब की तलाश में है। टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब अपने नाम किए थे। वहीं, कोलकाता नाइटराइडर्स तीन बार (2012, 2014 और 2024) चैंपियन बन चुकी है और इस सीजन में अपने प्रदर्शन को और मजबूत करना चाहेगी।

कुल मिलाकर यह मुकाबला आंकड़ों और मौजूदा फॉर्म के बीच दिलचस्प जंग होने वाला है। जहां एक ओर इतिहास मुंबई के पक्ष में है, वहीं हालिया प्रदर्शन के आधार पर कोलकाता को हल्के में नहीं आंका जा सकता। क्रिकेट फैंस के लिए यह मैच एक रोमांचक शुरुआत का वादा करता है।

मुंबई इंडियंस की टीम

रॉबिन मिंज, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेलटन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), राज बावा, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सैंटनर, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमार, जसप्रित बुमरा, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.

कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम

अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा.

मियामी ओपन 2026: यानिक सिनर ने ज्वेरेव को हराकर फाइनल में बनाई जगह, लेहेका से होगी भिड़ंत

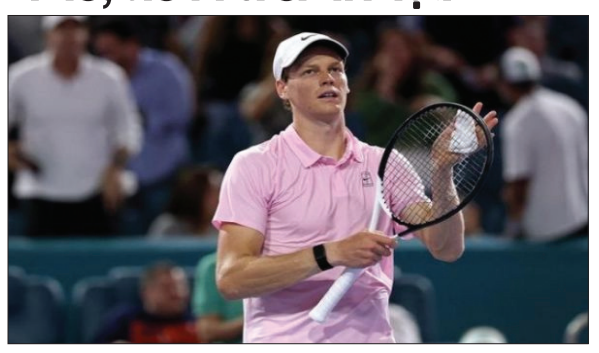

मियामी (एजेंसी)। मियामी ओपन 2026 में दुनिया के नंबर-2 टेनिस खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना चेक गणराज्य के जिरी लेहेका से होगा।

24 वर्षीय सिनर ने सेमीफाइनल में ज्वेरेव को 6-3, 7-6 (7/4) से हराया। यह ज्वेरेव के खिलाफ उनकी लगातार सातवीं जीत रही। इसके साथ ही सिनर ने मास्टर्स 1000 स्तर पर लगातार जीते गए सेट्स की संख्या 32 तक पहुंचा दी।

विंबलडन चैंपियन सिनर इससे पहले इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में भी ज्वेरेव को हरा चुके हैं और अब वह तीन साल में अपना दूसरा मियामी ओपन खिताब जीतने के करीब हैं। वह 2017 में रोजर फेडरर के बाद 'सनशाइन डबल' (इंडियन वेल्स और मियामी दोनों खिताब) हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बनने की कोशिश में हैं।

दूसरी ओर, 21वीं वरीयता प्राप्त लेहेका ने फ्रांस के आर्थर फिल्स को एकतरफा मुकाबले में 6-2, 6-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लेहेका ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक एक भी सेट नहीं गंवाया है और यह उनका पहला एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल होगा।

हालांकि, लेहेका का रिकॉर्ड सिनर के खिलाफ अच्छा नहीं रहा है। दोनों के बीच अब तक खेले गए तीनों मुकाबलों में सिनर ने जीत दर्ज की है और लेहेका एक भी सेट नहीं जीत सके हैं।

Also Read - देवरिया पुलिस ने 119 वाहनों का किया ई-चालान

महिला वर्ग में दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी आर्यना सबालेंका भी 'सनशाइन डबल' पूरा करने की कोशिश में हैं। वह फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ के खिलाफ अपने खिताब का बचाव करेंगी।

लेहेका ने मैच के बाद कहा कि वह इस प्रदर्शन से बेहद खुश हैं और पूरे सीजन की मेहनत का नतीजा अब देखने को मिल रहा है। वह अपने करियर के तीसरे एटीपी खिताब की तलाश में हैं।

यह फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, जहां अनुभवी और शानदार फॉर्म में चल रहे सिनर का सामना युवा और आत्मविश्वास से भरे लेहेका से होगा।

धोनी आईपीएल के शुरुआती मैचों से बाहर हुए

चेन्नई (एजेंसी)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों से बाहर हो गये हैं। धोनी के बाहर होने से टूर्नामेंट शुरु होने से पहले ही सीएसके की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। इसका कारण है कि धोनी टीम का हौंसला बढ़ाने के साथ ही उसे मार्गदर्शन भी देते रहे हैं। वह पिंडली में आये खिंचाव के कारण अभी रिहैबिलिटेशन के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में उनका शुरुआत से खेलना संभव नहीं है। सीएसके का मैच 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें टीम को उनकी कमी खलेगी।

धोनी के बाहर होने से साफ है कि अब सैमसन उनकी जगह पर विकेटकीपर रहेंगे। सीएसके अपना पहला मुकाबला सोमवार को राजस्थान रॉयल्स ये खेलेगी। उसे पहले दो सप्ताह में पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स से भी खेलना है। धोनी के नहीं होने से विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन अब विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

इस सत्र से पहले सैमसन को सीएसके ने ट्रेड डील के जरिये हासिल किया था। अब वह कप्तान रितुराज गायकवाड़ के साथ पारी की शुरुआत भी करेंगे। धोनी ने पिछले साल सभी मैच खेले थे हालांकि वह घुटने की परेशानी क कारण निचले क्रम पर उतरे थे। ऐसे मे उन्हें काफी कम गेंदें खेलने को मिलती है।

धोनी के अलावा सीएसके को तेज गेंदबाज नाथन एलिस की कमी भी खलेगी। उनकी जगह स्पेंसर जॉनसन को शामिल किया है। पिछले साल सीएसके का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और वह सबसे निचले स्तर पर रही थी। अब देखना है कि इस बार सीएसके क्या करती है।

अपनी पत्नियों के कारण खिलाड़ी लेते हैं संन्यास.., योगराज सिंह का विवादित बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अक्सर अपने अजीबो-गरीब बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने ये बयान खिलाड़ियों की पत्नियों को लेकर दिया है जिससे वो आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। योगराज ने साफ कहा कि उम्र को खिलाड़ी के प्रदर्शन से जोड़ना गलत है। उनके मुताबिक फिटनेस और प्रदर्शन ही किसी खिलाड़ी के करियर का असली पैमाना होना चाहिए, ना कि उम्र।

इनसाइड स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में योगराज सिंह ने कहा कि, भारत में लोग 40 की उम्र के बाद खुद को बूढ़ा मानने लगते हैं, महिलाएं 30 के बाद कहती हैं कि अब हम फिट नहीं रह सकते, बच्चे बड़े हो गए हैं। लेकिन खेल को उम्र से जोड़ना बिल्कुल गलत है।

योगराज सिंह ने कहा कि, अक्सर घर की महिलाएं, पत्नियां आपको समझाने लगती हैं कि अब रिटायर हो जाओ, परिवार और बच्चों पर ध्यान दो। मेरा मानना है कि महिलाओं को खिलाड़ी और उसके करियर के बीच नहीं आना चाहिए। एक खिलाड़ी और एक फकीर का कोई धर्म या वर्ग नहीं होता, वे भगवान के होते हैं। जब तक वे जिंदा हैं बहुत कुछ कर सकते हैं।

वहीं योगराज सिंह ने विराट कोहली और रोहित शर्मा पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि खिलाड़ियों को उम्र नहीं, बल्कि अपने प्रदर्शन से जवाब देना चाहिए। योगराज ने अपने बेबाक अंदाज में कहा कि, रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी युवा खिलाड़ी हैं और रिटायर होने की सोच रहे हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पर दुनिया को दिखाओ की तुम सबसे बेहतरीन हो, तुम अपरिहार्य हो।

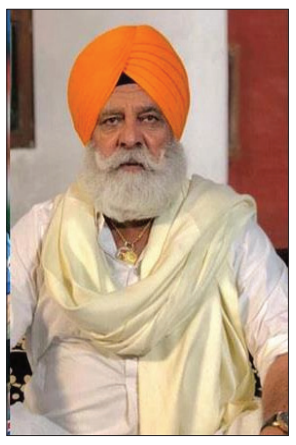

बांग्लादेश की नई सरकार ने आईपीएल प्रसारण पर रोक हटाई

ढाका। बांग्लादेश की नई सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के प्रसारण पर लगी रोक हटा दी है। इससे पहले की यूनुस सरकार ने ये रोक लगायी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार नये सूचना और प्रसारण मंत्री जहीर उद्दीन स्वपन ने कहा है कि बांग्लादेश में आगामी आईपीएल सत्र के प्रसारण पर कोई रोक नहीं है। जहीर उद्दीन स्वपन ने कहा, आईपीएल प्रसारण के लिए हालांकि अभी तक किसी ने भी हमसे आवेदन नहीं किया है। हम खेल में राजनीति को नहीं मिलाना चाहते। ऐसे में अगर कोई चैनल आईपीएल के प्रसारण के लिए हमसे आवेदन करता है, तो हम उस पर विचार करेंगे। वहीं इससे पहले, युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री अमीनुल हक ने कहा था कि वह पिछली अंतरिम सरकार की ओर से आईपीएल प्रसारण पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अधिकारियों से बात करेंगे।प्रसारण मंत्री ने कहा कि हम किसी को भी इसके प्रसारण से नहीं रोकेंगे। अगर स्टार स्पोर्ट्स इसका प्रसारण करना चाहता है, तो वह कर सकता है। अगर हमारे चैनलों में से कोई इसका प्रसारण करना चाहता है, तो हम किसी को नहीं रोकेंगे। बांग्लादेश के केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के कार्यालय सचिव, रेजाउल करीम लबलू का कहना है कि वे स्टार स्पोर्ट्स को आईपीएल का प्रसारण करने से नहीं रोकेंगे, हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला है।

आईपीएल में अब कमेंटर की भूमिका निभा रहे अश्विन

मुम्बई। दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस सत्र में अब कमेंट्री कर रहे हैं। अश्विन इस नई भूमिका में अपनी रणनीतिक समझ और विश्लेषण से दर्शकों पर कितना प्रभाव बनाते हैं ये देखना होगा। अश्विन का कमेंट्री के आने को एक अहम बदलाव माना जा रहा है। इससे साफ है कि अब कमेंट्री में मनोरंजन के साथ ही डेटा, मैच की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा होगी। गौरतलब है कि अश्विन ने अब तक आईपीएल में 221 मैच खेलकर 187 विकेट लिए हैं, ऐसे में उनका अनुभव कमेंट्री में भी नजर आयेगा। इस बार कमेंट्री पैनल काफी बड़ा रहेगा। वीरेंद्र सहवाग, एबी डिविलियर्स, इरफान पठान, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, फाफ डु प्लेसिस और अनिल कुंबले जैसे दिग्गज भी इस पैनल में शामिल हैं। इसके अलावा रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, केविन पीटरसन और इयोन मोर्गन भी अपने अलग अंदाज में रहेंगे। इस बार 12 भाषाओं में 160 से ज्यादा कमेंटेर दर्शकों पतक मैच का विवरण पहुंचाएंगे। अश्विन आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाजों में रहे हैं। उन्होंने 221 मैचों में 187 विकेट लिए और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 2010 और 2011 में ट्रॉफी जीती थी।

विराट के अलावा आरसीबी से सबसे अधिक मैच खेलने वालों में दो विदेशी भी शामिल

बेंगलुरु। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अब विराट कोहली ने आरसीबी की ओर से सबसे अधिक मैच खेले हैं। कोहली ने साल 2023 तक आरसीबी की कप्तानी करन के साथ ही कुल 143 मैच खेले। विराट के अलावा जिन खिलाड़ियों ने आरसीबी की ओर से सबसे अधिक मैच खेले है उनमें दो विदेशी खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस और डेनियल विटोरी भी शामिल हैं।

फाफ डु प्लेसिस : साल 2022 से 2024 के बीच डु प्लेसिस ने 42 मुकाबलों में आरसीबी की कप्तानी करते हुए 21 जीते और इतने ही मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। गंवाए।

डेनियल विटोरी : न्यूजीलैंड के इस दिग्गज खिलाड़ी ने साल 2011 से 2022 के बीच कुल 22 मुकाबलों में आरसीबी की कप्तानी की। इस दौरान 12 मैच जिताए और 10 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा।

अनिल कुंबले : दिग्गज स्पिनर ने साल 2009 से 2010 के बीच 26 मुकाबलों में आरसीबी की कमान संभाली। इस दौरान टीम ने 15 मैच जीते, जबकि 11 मुकाबलों को गंवा दिया।

राहुल द्रविड़ : यह खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में आरसीबी का पहला कप्तान रहा, जिन्होंने सिर्फ साल 2008 में इस टीम की कमान संभाली। इस दौरान 14 में से सिर्फ 4 ही मैच टीम को जिता सके। 10 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी।

ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 103 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई

सेंट किट्स (एजेंसी)। सेंट किट्स के बासेटेरे में शुक्रवार रात खेले गए पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 103 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। नई कप्तान सोफी मोलिन्यूक्स के नेतृत्व में टीम ने शानदार जीत दर्ज की।

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 341 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम की शुरुआत मजबूत रही और ओपनिंग जोड़ी ने 75 रन जोड़े। जॉर्जिया वोल ने 32 गेंदों में 42 रन बनाए, जबकि फोएबे लिचफील्ड ने 72 गेंदों पर 77 रनों की अहम पारी खेली। एलिस पेरी ने 46 गेंदों में 44 रन बनाकर टीम को मजबूती दी।

मध्यक्रम में कप्तान सोफी मोलिन्यूक्स ने 47 रन बनाए और निकोला कैरी (49) के साथ 91 रनों की साझेदारी की। अंत में जॉर्जिया वेयरहैम ने 42 रन बनाकर टीम को 300 के पार पहुंचाया। वेस्टइंडीज की ओर से अफी फ्लेचर ने 3 विकेट लिए, लेकिन काफी महंगे साबित हुईं।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही और टीम ने जल्दी विकेट गंवा दिए, जिसमें कप्तान हेले मैथ्यूज का विकेट भी शामिल था। अनुभवी बल्लेबाज स्टेफनी टेलर ने शानदार नाबाद 105 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, जो उनका 2021 के बाद पहला वनडे शतक था, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। चिनेल हेनरी ने 38 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से किम गर्थ ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, जबकि एश्ले गार्डनर ने भी अहम योगदान दिया। अंततः वेस्टइंडीज की टीम 238/8 तक ही पहुंच सकी और मुकाबला गंवा बैठी।

टाइगर वुड्स नशे में गाड़ी चलाने के बाद गिरफ्तार , आठ घंटे बाद हुए रिहा

न्यूयॉर्क। विश्व के शीर्ष गोल्फरों में शामिल रहे अमेरिका के टाइगर वुड्स को नशे में गाड़ी चलाने के कारण गिरफ्तार किया गया है हालांकि उन्हें आठ घंटे के बाद जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। वुड्स पर आरोप है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए उनकी कार फ्लोरिडा में अपने घर के करीब ही पलट गयी थी। उन्हें गिरफ्तार किये जाने के कुछ ही समय के बाद फ्लोरिडा की एक जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लोरिडा के कानून के अनुसार, वुड्स को कम से कम आठ घंटे जेल में बिताने पड़े। शुरुआती रिपोर्ट्स में मार्टिन काउंटी पुलिस के हवाले से कहा गया है कि जब वुड्स दोपहर करीब 2 बजे एक फ्लैटबेड ट्रक को तेजी से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनकी लैंड रोवर कार पलट गई। उस समय नशे में थे। उन्होंने पुलिस से जांच में सहयोगी भी नहीं किया और यूरीन जांच के लिए तैयार नहीं हुए। गिरफ्तारी के बाद वुड्स नशे में दिखे। मार्टिन काउंटी पुलिस ने शाम को वुड्स की एक गिरफ्तारी के समय ली गई तस्वीर जारी की, जिसमें उनकी आंखें लाल दिखाई दे रही थीं। उन्हें फ्लोरिडा की मार्टिन काउंटी जेल ले जाया गया था। मार्टिन काउंटी के शेरिफ जॉन बुडेंसिएक ने कहा वुड्स एक लैंड रोवर चला रहे थे। घर के पास एक सड़क पर एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में उनकी गाड़ी पलट गई। गाड़ी एक ट्रेलर से टकराई, सड़क से हट गई, और सड़क पर कुछ दूर घिसटने के बाद पलट गई। वुड्स पर पहले भी सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले दर्ज हैं हैं। इससे पहले फरवरी 2021 में उनका एसयूवी लॉस एंजिलिस की एक तटीय सड़क पर तेज रफ्तार में नियंत्रण से बाहर होकर सड़क से उतर गया था, जिसमें वह घायल भी हो गये थे।

बैडमिंटन और मैं तुम्हें बहुत याद करेंगे: पीवी सिंधु

नई दिल्ली (एजेंसी)। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने अपनी लंबे समय की प्रतिद्वंद्वी कैरोलिना मारिन को बैडमिंटन से संन्यास लेने के बाद एक भावुक संदेश में कहा कि बैडमिंटन और मैं तुम्हे बहुत याद करेंगे।

रियो 2016 की स्वर्ण पदक विजेता और तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन कैरोलिना मारिन ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज के जरिए अपने संन्यास की घोषणा की।

पीवी सिंधु ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया मंच इंटस्टग्राम पर स्पेन की कैरोलिना मारिन के संन्यास की घोषणा को लेकर कहा, 'कुछ प्रतिद्वंद्वी हमेशा के लिए आपकी यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। कैरोलिना उनमें से एक थीं। हम पहली बार एक-दूसरे के खिलाफ तब खेले थे जब हम मालदीव में 15 या 16 साल की लड़कियां थीं, और तब से हमने एक साथ कई मुकाबले खेले।'

उन्होंने कहा, 'सच कहूँ तो, कोर्ट पर तुम सचमुच बहुत

परेशान करने वाली थीं। लगातार चिल्लाना, तुम्हारी आक्रामकता, तुम्हारी छोटी-छोटी चालें–ये सब किसी को भी परेशान कर सकती थीं। लेकिन तुम्हारा कौशल, तुम्हारी गति और तुम्हारी लड़ने की भावना बेजोड़ थी। लोग बड़े-बड़े मुकाबलों को याद करते हैं, और उस तीसरे सेट में शटल उठाने को लेकर हमारे बीच हुई उस तीखी बहस को भी। मैं मानती हूं कि उस दिन मैं पूरी तरह से गुस्से में थी। लेकिन कुछ महीनों बाद, हम मैड्रिड में कॉफी पीते हुए एक-दूसरे के सामने बैठे थे बातें कर रहे थे, हँस रहे थे और उस पल हमारे बीच सिर्फ़ एक-दूसरे के लिए सम्मान था। यही है कैरोलिना, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी।'

सिंधु ने लिखा, 'मैं हमारी पीढ़ी के बीच बनी उस अद्भुत दोस्ती के लिए भी हमेशा आभारी रहूँगी। हमारी लड़कियों के बैच ने 'विमेंस सिंगल्स' को मुकाबले के लिए एक बहुत ही खास जगह बना दिया था; सच कहूँ तो, मुझे नहीं पता कि बैडमिंटन के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ है या भविष्य में कभी होगा। हर मुकाबले के लिए, हर सीख के लिए, और सबसे बढ़कर–हमारी दोस्ती के लिए–तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारे संन्यास के बाद के जीवन के लिए ढेर सारी खुशियों की कामना करती हूं, कैरोलिना।'

नवनीत कौर ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिलने पर जताई खुशी, टीम को किया समर्पित

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार फॉरवर्ड नवनीत कौर ने हॉकी इंडिया आठवें वार्षिक अवॉर्ड्स 2025 में 'प्लेयर ऑफ द ईयर (महिला)' का प्रतिष्ठित सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्हें यह सम्मान हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवॉर्ड के तहत प्रदान किया गया।

नवनीत कौर के लिए बीता साल बेहद शानदार रहा, जहां उन्होंने भारतीय टीम के लिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। हैदराबाद में आयोजित एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप क्वालीफायर में उन्होंने अहम भूमिका निभाते हुए भारत को रजत पदक दिलाने में योगदान दिया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने चार गोल किए और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी चुनी गईं।

इसके अलावा महिला एशिया कप 2025 में भी नवनीत का प्रदर्शन दमदार रहा, जहां भारत ने रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता में उन्होंने छह गोल दागे। इसी दौरान उन्होंने अपने करियर का एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए 200 अंतरराष्ट्रीय मैच भी पूरे किए।

पुरस्कार मिलने के बाद नवनीत कौर ने कहा, 'इस सम्मान को पाकर मैं बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। यह उपलब्धि मेरी टीम के साथियों के सहयोग और विश्वास के बिना संभव नहीं थी। मैं हॉकी इंडिया का भी धन्यवाद करना चाहती हूं, जो हर साल इस तरह का मंच उपलब्ध कराता है, जिससे खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है।'

आगामी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स को लेकर उन्होंने कहा, 'आने वाला समय काफी व्यस्त रहने वाला है। नेशंस कप, वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट हमारे सामने हैं। हमारा कैंप जल्द शुरू होगा और हम अपनी कमजोरियों पर काम कर टीम के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे।'

अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को लेकर नवनीत ने कहा, 'मैं अपने खेल में लगातार सुधार करना चाहती हूं। अभी तक के प्रदर्शन से संतुष्ट हूं, लेकिन आगे और बेहतर करने की गुंजाइश है। बड़े टूर्नामेंट चार साल में एक बार आते हैं, इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं।'

आगामी बड़े टूर्नामेंट्स को देखते हुए नवनीत कौर पूरी तरह फोकस्ड हैं और भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही हैं।

फीफा के टूर्नामेंटों में हिस्सा लेने वाली टीमों को महिला कोच रखना होगा अनिवार्य : फीफा

ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड)। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में महिला कोचों की संख्या में वृद्धि को लेकर फीफा ने कुछ नए नियम घोषित किये है। इसके तहत अब फीफा के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हर टीम को कम से कम एक महिला मुख्य या सहायक कोच रखना अनिवार्य होगा। हाल ही में हुई एक काउंसिल मीटिंग के बाद फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) ने कुछ नए नियम घोषित किए हैं। इन नियमों का मकसद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में महिला कोचों की संख्या को बढ़ाना है। नए नियमों के अनुसार फीफा के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाली हर टीम के लिए यह जरूरी होगा कि उसके पास कम से कम एक महिला हेड कोच या असिस्टेंट कोच हो। इसके अलावा, टीम के साथ बेंच पर एक और महिला स्टाफ सदस्य का होना भी जरूरी होगा। फीफा की मुख्य फुटबॉल अधिकारी जिल एलिस ने कहा, 'आज कोचिंग के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या काफी कम है। हमें इस बदलाव की रफ्तार तेज करने के लिए और अधिक कोशिशें करनी होंगी। हमें महिलाओं के लिए कोचिंग के साफ रास्ते बनाने होंगे, उनके लिए अधिक मौके पैदा करने होंगे, और उन्हें खेल के मैदान के किनारे (साइडलाइन) पर ज्यादा से ज्यादा पहचान दिलानी होगी। फीफा के ये नए नियम और इनके साथ चलाए जा रहे खास डेवलपमेंट प्रोग्राम, महिला कोचों की आज की और आने वाली पीढ़ियों में एक बड़ा निवेश साबित होंगे।'

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका में प्रवासियों को बिना जमानत हिरासत में रखने पर बड़ा फैसला

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि सरकार प्रवासियों को बिना जमानत के हिरासत में रख सकती है। यह फैसला 8वीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने दिया, जिसने पहले के निचली अदालत के आदेश को पलट दिया। पहले कहा गया था कि बिना दस्तावेजों के पकड़े गए लोगों को जमानत सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। यह मामला मेक्सिको के नागरिक जोकिन हेरेरा एविला से जुड़ा था, जिन्हें 2025 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जमानत की मांग की थी, लेकिन अब अदालत ने कहा कि कानून के तहत सरकार उन्हें हिरासत में रख सकती है। यह दूसरा बड़ा फैसला है जो ट्रंप प्रशासन के सख्त इमिग्रेशन रुख के पक्ष में गया है। अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने इसे बड़ी जीत बताया है। हालांकि, मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे हजारों लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। यह मामला अब अमेरिका में कानूनी और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।

एयर कनाडा सीईओ पर विवाद, फ्रेंच न बोल पाने पर मांगी माफी

टोरंटो, एजेंसी। कनाडा की बड़ी एयरलाइन एयर कनाडा के सीईओ माइकल रूसो को एक गंभीर विमान हादसे के बाद फ्रेंच भाषा में बात न कर पाने को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क में हुए इस हादसे में दो पायलटों की मौत हो गई थी, जिनमें से एक क्यूबेक का फ्रेंच भाषी था। इसके बाद सीईओ ने एक शोक संदेश जारी किया, लेकिन वह पूरी तरह अंग्रेजी में था, जिसमें केवल 'शुभ प्रभात' और 'धन्यवाद' जैसे दो फ्रेंच शब्द ही शामिल थे। इस पर क्यूबेक के नेताओं और आम लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी इसे संवेदनशीलता की कमी बताया और कहा कि देश की दोनों आधिकारिक भाषाओं का सम्मान जरूरी है। क्यूबेक के प्रीमियर ने तो सीईओ से इस्तीफा तक मांग लिया। अब माइकल रूसो ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें दुख है कि उनकी भाषा की कमी की वजह से हादसे से ध्यान हट गया। उन्होंने स्वीकार किया कि कई वर्षों से कोशिश करने के बावजूद वे अभी भी फ्रेंच में सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे सीखने की कोशिश जारी रखेंगे। यह मामला इसलिए भी बड़ा बन गया क्योंकि एयर कनाडा का मुख्यालय क्यूबेक में है, जहां लगभग 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। इससे पहले भी माइकल रूसो को इसी मुद्दे पर आलोचना झेलनी पड़ी थी।

अमेरिका में एयरफोर्स बेस के बाहर विस्फोटक मामला, भाई-बहन पर आरोप

फ्लोरिडा, एजेंसी। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित मैकडिल एयरफोर्स बेस के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में भाई-बहन एलन झेंग और एन मैरी झेंग के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफबीआई के अनुसार, 20 साल का एलन झेंग चीन भाग गया है, जबकि उसकी बहन को हिरासत में लिया गया है। एलन पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, खतरनाक विस्फोटक बनाने और बिना रजिस्ट्रेशन के हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं उसकी बहन पर सबूत छिपाने और मदद करने का आरोप है। यह घटना 16 मार्च को सामने आई थी जब एयरफोर्स बेस के बाहर एक संदिग्ध पैकेट मिला। इसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। यह बेस बेहद संवेदनशील है क्योंकि यहां से अमेरिका की मध्य-पूर्व और एशिया में सैन्य गतिविधियां संचालित होती हैं। इस घटना के बाद एक अन्य व्यक्ति को भी धमकी भरे फोन कॉल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, हालांकि उसका इस विस्फोटक से कोई सीधा संबंध नहीं बताया गया है। ईरान युद्ध के चलते पहले से ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, ऐसे में इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है।

स्पेन में 25 साल की महिला ने ली इच्छामृत्यु, देशभर में बहस तेज

मैड्रिड, एजेंसी। स्पेन में 25 साल की नोएलिया कास्टिलो का इच्छामृत्यु लेना पूरे देश में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। नोएलिया कैस्टिलो ने लंबे कानूनी संघर्ष के बाद यह अधिकार हासिल किया और बार्सिलोना में उन्हें जीवन समाप्त करने की अनुमति दी गई। कास्टिलो पिछले कई वर्षों से मानसिक बीमारी और गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रही थीं। एक आत्महत्या के प्रयास के बाद वे व्हीलचेयर पर आ गई थीं। उन्होंने 2024 में इच्छामृत्यु के लिए आवेदन किया, जिसे मेडिकल बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि, उनके परिवार ने इस फैसले का विरोध किया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई अपीलों के बाद स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने कास्टिलो के पक्ष में फैसला सुनाया। मौत से एक दिन पहले उन्होंने कहा कि वे अब और दर्द सहन नहीं कर सकतीं और शांति चाहती हैं। वहीं, उनके परिवार का कहना है कि सरकार ने उनकी बेटी को बचाने में नाकामी दिखाई।

कनाडा में खालिस्तानियों के बुरे दिन! झंडे फहराने पर बैन, मंदिरों के बाहर उपद्रव पर जेल; बिल पास

ओटावा, एजेंसी। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स ने बुधवार को एक ऐतिहासिक बिल पास किया है, जिसके तहत बब्बर खालसा जैसे खालिस्तानी समूहों के झंडे और अन्य आतंकवादी प्रतीकों का प्रदर्शन करना गैरकानूनी हो जाएगा। साथ ही, धार्मिक स्थलों के बाहर लोगों को डराना-धमकाना या उनका रास्ता रोकना भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा।

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली कनाडा की लिबरल सरकार का राजनीतिक रूप से विवादास्पद नया घृणा-विरोधी विधेयक (एंटी-हेट बिल) 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में अपनी अंतिम बाधा पार कर चुका है और अब इसे मंजूरी के लिए सीनेट में भेजा जाएगा। इस बिल सी-9 को 'कॉम्बैटिंग हेट एक्ट' नाम दिया गया है। यह क्रिमिनल कोड (आपराधिक संहिता) में नए अपराधों का प्रस्ताव करता है। इसके तहत कुछ विशेष घृणा या आतंकवाद से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल करके सार्वजनिक रूप से पहचान योग्य समूहों के खिलाफ जानबूझकर नफरत को बढ़ावा देना अपराध माना जाएगा। यह विधेयक बुधवार रात को ब्लॉक क्यूबेकोइस पार्टी के समर्थन से तीसरे चरण की वोटिंग (थर्ड रीडिंग) में पारित हो गया। मुख्य विपक्षी दल कंजर्वेटिव और एनडीपी ने इस कानून के खिलाफ मतदान किया।

बिल से जुड़ी मुख्य बातें : कॉम्बैटिंग हेट एक्टः इस बिल को

औपचारिक रूप से यही नाम दिया गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स से पास होने के बाद अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए कनाडाई सीनेट में भेजा जाएगा।

आतंकवाद के महिमामंडन पर रोकः यह नया कानून 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की आड़ में खालिस्तानी झंडे फहराने और खुलेआम खालिस्तानी साहित्य बांटकर आतंकवाद का महिमामंडन करने पर सख्त पाबंदी लगाता है। आतंकी संगठनों पर नकेलः इस बिल के लागू होने से बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे संगठनों के लिए सार्वजनिक रूप से काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रहे कि इन दोनों ही संगठनों को भारत और कनाडा में आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है।

'धार्मिक छूट' हटाने पर हुआ समझौता : लिबरल पार्टी को ब्लॉक क्यूबेकोइस का समर्थन एक विशेष शर्त पर मिला। लिबरल्स ने बिल में एक ऐसा क्लॉज शामिल किया है जो कनाडा के हेट स्पीच (घृणा भाषण) कानून से 'धार्मिक छूट' को खत्म कर देगा। वर्तमान में, आपराधिक संहिता में हेट स्पीच के लिए एक छूट का प्रावधान है। इसके अनुसार, 'यदि कोई व्यक्ति सद्भावपूर्ण तरीके से, किसी धार्मिक विषय पर अपनी राय रखता है या किसी धार्मिक ग्रंथ में अपने विश्वास के आधार पर तर्क देकर अपनी बात स्थापित करने का प्रयास करता है' तो उसे हेट स्पीच नहीं माना जाता है। नया बिल इस छूट को खत्म कर देगा।

कंजर्वेटिव्स ने इस धार्मिक छूट को हटाने वाले प्रावधान का कड़ा विरोध करते हुए इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर 'हमला' करार दिया है। कई धार्मिक समूहों ने भी इसे हटाए जाने पर गहरी चिंता जताई है। कैनेडियन सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन जैसे नागरिक अधिकार समूहों का भी मानना है कि यह बिल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को आपराधिक बना सकता है और सरकार से असहमति जताने वाली आवाजों को दबा सकता है। सरकार का पक्ष और अगला कदम इस बिल को पेश करने वाले और ब्लॉक क्यूबेकोइस के साथ समझौता कराने वाले न्याय मंत्री सीन फ्रेजर ने विरोधियों की आलोचनाओं को खारिज किया है। उनका कहना है कि नया कानून किसी की आस्था को अपराध नहीं बनाएगा। अब यह बिल सीनेट (उच्च सदन) के पास जाएगा, जहां कानून बनने से पहले इसका गहन अध्ययन किया जाएगा। सीनेट के पास अभी भी इस कानून में बदलाव के लिए अपने सुझाव देने का अधिकार है। भारतीय-कनाडाई समुदाय के लिए बड़ी राहत इस बिल को भारतीय-कनाडाई समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह समुदाय पिछले कई दशकों से कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा उत्पीड़न का सामना कर रहा था। खालिस्तानी समर्थकों द्वारा अक्सर हिंदू मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थानों में तोड़फोड़ की जाती रही है और वहां जाने वाले श्रद्धालुओं के रास्ते बंद किए जाते रहे हैं। खालिस्तान आंदोलन और कनाडा में उसका सुरक्षित ठिकाना खालिस्तान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत के पंजाब राज्य को अलग कर सिखों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है।

आने वाले महीनों में ऑस्ट्रेलिया की तेल आपूर्ति और मुश्किल होगी : पीएम अल्बनीज

कैनबरा, एजेंसी। ईरान और अमेरिका-इजरायल में जारी हमलों की वजह से जो तनाव पैदा हुआ है, उसने तेल और गैस को लेकर दुनिया के तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शुक्रवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया की फ्यूल सप्लाई शॉर्ट टर्म में अच्छी लग रही है लेकिन आने वाले महीनों में यह और मुश्किल हो जाएगी। देश में बढ़ते फ्यूल संकट पर कैनबरा में पार्लियामेंट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए पीएम अल्बनीज ने कहा कि सरकार सबसे मजबूत योजना बनाने के लिए रात-दिन काम कर रही है और जो भी हो सकता है उसके लिए पूरी तरह तैयार है। अल्बनीज ने मलेशिया और बड़े आसियान इलाके के साथ अपने सकारात्मक संबंधों का जिक्र किया। बता दें, मलेशिया ऑस्ट्रेलिया को तेल का एक अहम सप्लायर है।

जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और तेल की सप्लाई वैसी ही बनी हुई है। बोवेन ने कहा, 'सरकार ने हमेशा माना है कि क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में असली और स्वीकार ना की जा सकने वाली कमी है क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है और उस मजबूत घरेलू सप्लाई में समय लगा है। अल्बनीज तेल के संकट की स्थिति को लेकर चर्चा करने के लिए सोमवार को एक नेशनल कैबिनेट मीटिंग भी बुलाएंगे। इससे पहले दिन में, विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने सरकार से तीन महीने के लिए फ्यूल एक्साइज को अस्थायी तौर पर आधा करने की मांग की थी। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने बुधवार को माना कि देश भर के करीब 470 सर्विस स्टेशनों में कम से कम एक तरह का फ्यूल खत्म हो गया है। इससे पहले 24 मार्च को, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एबीसी) ने रिपोर्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया में अब सिर्फ दो घरेलू रिफाइनरियां चल रही हैं, जबकि इसका 80 फीसदी से ज्यादा पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें से लगभग सारा एशिया से आता है। एबीसी ने यह भी बताया था कि एशियाई रिफाइनर जो कच्चा तेल इस्तेमाल करते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है और इसे मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भेजा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया था कि ग्लोबल तेल बाजार में सप्लाई में भारी रुकावट आ रही है और बाजार अभी भी इस झटके के समय और नुकसान को कम आंक रहे हैं। इसमें कहा गया था कि अगर होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल भी जाता है, तो शिपिंग बीमा जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा, जिसका मतलब है।

जी7 की बैठक से अलग कनाडा की विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, पश्चिम एशिया और होर्मुज संकट पर हुई बात

ओटावा, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी संकट और उसके दुनिया पर पड़ रहे असर को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ अहम बैठक की। दोनों नेताओं की यह बैठक जी7 की बैठक से अलग हुई। जयशंकर गुरुवार को जी7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने फ्रांस पहुंचे। बैठक के बाद कनाडा की विदेश मंत्री ने एक्स पर साझा एक पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने इस वर्ष की शुरुआत में पीएम कार्नी के भारत दौरे पर आगे बढ़ाई गई साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की।

पश्चिम एशिया संकट के अलावा इन मुद्दों पर हुई बात : आनंद ने कहा कि बैठक में व्यापार, पश्चिम एशिया की स्थिति और दोनों देशों के सहयोग को और मजबूत करने पर बात हुई। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण खनिज, कृषि और शिक्षा पर भी चर्चा हुई। दो दिवसीय जी-7 बैठक में जयशंकर पश्चिम एशिया संकट पर विशेष ध्यान देते हुए इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहे। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित यह संकीर्ण समुद्री मार्ग वैश्विक तेल और एलएनजी आपूर्ति के लिए अहम है और दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस व्यापार यहीं से गुजरता है। पश्चिम एशिया संकट के चलते ईरान द्वारा इसे बाधित किया गया, जिसके चलते वैश्विक तेल और गैस कीमतों में तेज उछाल देखा गया है।

जी7 की बैठक में पश्चिम एशिया मुद्दा छाया रहा : यह जी-7 बैठक 26-27 मार्च को फ्रांस में आयोजित की जा रही है। ग्रुप ऑफ 7 में दुनिया की सात प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। यूरोपीय संघ भी इस समूह का सदस्य है। भारत के अलावा, फ्रांस ने सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और ब्राजील को भी इस बैठक में आमंत्रित किया है। जी-7 वैश्विक आर्थिक, वित्तीय और भू-राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा और समन्वित कार्रवाई के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में काम करता है।

पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन की संयुक्त राष्ट्र में कड़ी निंदा; अफगान नागरिकों की मौत पर भी चिंता

न्यूयार्क, एजेंसी। तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं पर जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 61वें सत्र में पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन पर कड़ी निंदा की गई। सत्र के दौरान आर्थिक विकास और मानवाधिकारों का हनन शीर्षक से चर्चा हुई। इस दौरान पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हमलों में बेकसूर अफगान नागरिकों की मौत को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई।

इस दौरान जापानी मानवाधिकार कार्यकर्ता शुन फुजिकी बोले, करीब 27 वैश्विक मानवाधिकार समझौतों से बंधे होने के बावजूद इस देश में गंभीर उल्लंघन जारी हैं। उन्होंने जबरन गायब किए जाने, यातना और हत्याओं की व्यापक रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि कई नागरिक या तो देश छोड़कर भाग रहे

हैं या भय में जी रहे हैं। इंटरनेशनल करियर सपोर्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चर्चा में वैश्विक विशेषज्ञों ने भाग लिया और इस बात का विश्लेषण किया कि एशियाई देशों में तीव्र आर्थिक प्रगति किस प्रकार लगातार हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को अक्सर नजरअंदाज कर देती है।

विशेषाधिकारों के वैश्विक मानक मानने होंगे : वक्ताओं ने श्रम अधिकारों के हनन व अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश और नागरिक कल्याण को प्राथमिकता न देने वाली विकास नीतियों के व्यापक सामाजिक नतीजों पर प्रकाश डाला। जापान के शुन फुजिकी ने जोर दिया कि हमारा उद्देश्य पाकिस्तान को अलग-थलग करना नहीं, फिर भी पाकिस्तान को व्यापारिक विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए वैश्विक मानकों का पालन करना होगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रति प्रतिबद्धता की गंभीर कमी भी उजागर की। भारत में समानता और समावेश के मुद्दे पर चर्चा यूएनएचआरसी के 61वें सत्र में संभली ट्रस्ट के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान ने नस्लवाद, भेदभाव और असहिष्णुता की वैश्विक चुनौतियों की पर ध्यानाकर्षित करते हुए समावेशिता के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, नस्ली भेदभाव और विदेशियों के प्रति घृणा विश्व स्तर पर सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।

ये मुद्दे न केवल मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी बाधित करते हैं, जिससे शिक्षा, रोजगार और न्याय तक पहुंच में समान अवसरों में बाधाएं पैदा होती हैं। वह बोले, भारत के ढांचे में सांविधानिक सुरक्षा उपाय समानता को बढ़ावा देते हैं और नागरिकों को भेदभाव से बचाते हैं। चौहान में जोधपुर में किए गए कार्यों की भी जानकारी दी।

ईरान युद्ध के बीच बदलते समीकरणों के चलते चीन ने बदला अपना रुख

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सरकार के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चीन ईरान विवाद पर अपने नजरिए को बदल रहा है। पूर्व अधिकारी ने कहा कि चीन अमेरिका के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की तैयारी के लिए तनाव कम करने के लिए समर्थन का संकेत दे रहा है। यह बात ऐसे समय में आई है जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने चीन जाने का प्लान बना रहे हैं, जबकि खाड़ी में लड़ाई बढ़ती जा रही है। पूर्व अधिकारी ने कहा, 'यह बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रपति इस बड़े युद्ध के बीच में चीन जाने के लिए तैयार थे।' उन्होंने इस समय को बहुत अजीब बताया। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल में चीन के दौरे पर जाने वाले थे। हालांकि, हालिया हमलों और तनाव की वजह से अब चर्चा हो रही है कि वह मई में चीन दौरे पर जाएंगे। ट्रंप के चीन दौरे को लेकर अधिकारी ने कहा कि एशिया भर के देश प्रस्तावित समिट पर करीब से नजर रख रहे हैं, क्योंकि इससे इलाके की स्थिरता और आर्थिक हालात पर असर पड़ सकता है। अधिकारी ने कहा, 'एशिया का हर देश देख रहा है और उम्मीद कर रहा है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप चीन आएंगे तो क्या उम्मीद की जा सकती है।' अमेरिकी सरकार के एक दूसरे पुराने अधिकारी ने कहा कि हाल की आर्थिक बातचीत के बाद इस लड़ाई ने दोनों पक्षों को फिर से सोचने का मौका दिया है। पेरिस में हुई बातचीत का जिक्र करते हुए अधिकारी ने कहा, 'खाड़ी में ऑपरेशन दोनों पक्षों के लिए ज्यादा समय पाने का एक पॉलिटिकल कवर बन गया।' अधिकारी ने कहा कि चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मेजबानी के लिए तैयार होने का संकेत देना जारी रखा है। हालांकि, अभी इस दौरे से संबंधित डिटेल्स को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ है। अधिकारी ने कहा, 'चीनियों ने आज सुबह कमोबेश संकेत दिया कि वे अभी भी उनकी (ट्रंप की) मेजबानी के लिए तैयार होंगे, लेकिन तारीखें कन्फर्म नहीं कीं।' इसके साथ ही, हाल की डिप्लोमैटिक बातचीत के बाद लड़ाई पर चीन के मैसेज में बदलाव के संकेत दिखे हैं। एक तीसरे पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने कहा, 'शांति को बढ़ावा देने, ईरानियों को बातचीत की टेबल पर लाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।' उन्होंने इस बदलाव को छोटा लेकिन ध्यान देने लायक बताया। अधिकारी ने आगे कहा कि अमेरिका के लिए एक शांति प्रस्ताव था, जिससे पता चलता है कि बीजिंग उच्च स्तरीय बातचीत से पहले हालात को स्थिर करना चाहता है। बदलते हालात ईरान विवाद और बड़ी अमेरिकी-चीन बातचीत के बीच के संबंध को भी दिखाते हैं। दूसरे अधिकारी ने एजेंडा के संभावित विस्तार की ओर इशारा करते हुए कहा, 'अमेरिका के बातचीत करने वाले अब किस हद तक, ईरानी तेल की चीनी खरीद जैसी बातें उठाना शुरू करेंगे।' अधिकारी ने ईरान को चीन के संभावित समर्थन के बारे में भी चिंता जताई। अधिकारी ने कहा, 'झगड़े से पहले, चीनियों ने ईरानियों को एंटी शिप मिसाइल बेचने की बात की थी।' उन्होंने कहा कि ऐसे विकास पर करीब से नजर रखी जाएगी। इन मुश्किलों के बावजूद, दोनों पक्ष बातचीत बनाए हुए दिख रहे हैं। समिट को लेकर चीन की ओर से मिल रहे संकेतों को लेकर अधिकारी ने कहा, 'मुझे लगता है यह उनके हित में है और यह हमारे भी हित में है।

मेक्सिको की खाड़ी में तेल का रिसावः 600 किलोमीटर तक फैला प्रदूषण, सात प्राकृतिक रिजर्व प्रभावित

मैक्सिको सिटी, एजेंसी। मेक्सिको की खाड़ी में मार्च की शुरुआत में तेल का भारी रिसाव हुआ। अब इसका प्रदूषण 600 किलोमीटर से ज्यादा बड़े इलाके में फैल गया है। मेक्सिकन अधिकारियों ने बताया कि यह रिसाव एक ऐसे जहाज से शुरू हुआ जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इसमें दो प्राकृतिक स्रोत भी शामिल हैं। इस घटना ने सात प्राकृतिक रिजर्व क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया है।

नौसेना सचिव एडमिरल रायमुंडो मोरालेस ने मीडिया वार्ता में बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों और जांच से रिसाव के तीन मुख्य ठिकानों का पता चला है। पहला स्रोत वेराक्रूज राज्य के कोत्जाकोआल्कोस बंदरगाह के पास खड़ा एक जहाज है। इस जहाज की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि उस समय वहां 13 जहाज मौजूद थे। दूसरा स्रोत इसी बंदरगाह से 8 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहाँ से कच्चा तेल प्राकृतिक रूप से निकलता है। तीसरा स्रोत कैम्पेचे की खाड़ी में स्थित एक और प्राकृतिक रिसाव वाली जगह है। मोरालेस ने स्वीकार किया कि तेल का रिसाव अब भी जारी है। कैम्पेचे की खाड़ी में स्थित कंटारेल से सबसे ज्यादा रिसाव हो रहा है। यहां से प्राकृतिक रूप से तेल निकलता रहता है। हालांकि, पिछले महीने में प्रदूषकों का बहाव काफी ज्यादा रहा है।

कई राज्यों के लंबे तट प्रभावित : इस रिसाव ने वेराक्रूज और टबैस्को राज्यों के 200 किलोमीटर लंबे तट को प्रभावित किया है। अब तक 430 टन हाइड्रोकार्बन इकट्ठा किया जा चुका है। मामले पर पर्यावरण सचिव एलिसिया बारसेना ने बताया कि इस रिसाव से वेराक्रूज और ताबास्को राज्यों के सात संरक्षित प्राकृतिक रिजर्व प्रभावित हुए हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें पर्यावरण को किसी भी तरह का गंभीर नुकसान होता हुआ नहीं दिखा है। समुद्री जीवों को पहुंच रहा नुकसान दूसरी तरफ, समुद्री संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ओशियाना ने अलग जानकारी दी है। संस्था ने बताया कि इस रिसाव से समुद्री कछुए, एक मैनेट (समुद्री गाय) और कई मछलियां मारी गई हैं। साथ ही 17 मूंगा चट्टानों (रीफ) को भी नुकसान पहुंचा है। पर्यावरण अधिकारियों ने भी माना कि समुद्री कछुए, पक्षी और मछलियों समेत छह प्रजातियां इस प्रदूषण से प्रभावित हुई हैं। तेल का असर लॉस टक्सटलास बायोस्फीयर रिजर्व, वेराक्रूज रीफ सिस्टम नेशनल पार्क, लेचुगुइलास और टोटोनाकापन जैसे कई सुरक्षित क्षेत्रों में देखा गया है। टबैस्को के सेंटला वेटलैंड्स में भी सफाई का काम किया जा रहा है। बता दें कि इससे पांच महीने पहले भी वेराक्रूज में भारी बारिश और बाढ़ के कारण वेराक्रूज में ही एक पाइपलाइन टूट गई थी।

अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने पर दिया जोर, रिश्ते को 'जटिल' बताया

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के वरिष्ठ विधायकों और अधिकारियों ने पाकिस्तान के साथ अधिक गहरे और परिणाम-उन्मुख संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है और इस रिश्ते को 'जटिल' बताया है। कैपिटल हिल पर बुधवार को टाम सुओजी और जैक बर्गमैन द्वारा आयोजित एक द्विदलीय संगोष्ठी में 200 से अधिक नीति-निर्माताओं, राजनयिकों और विशेषज्ञों ने अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों की दिशा का आकलन किया। सुओज़ी ने कहा, 'ऐसे समय में जब हमारा देश और दुनिया बढ़ती विभाजन की भावना महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान जैसे महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना पहले से कहीं अधिक जरूरी है।' संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध जटिल रहे हैं। बर्गमैन ने विभाजनों के पार संवाद और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'ऐसी एकता संयोग से नहीं होती। यह बातचीत से शुरू होती है। यह इस साझा विश्वास से शुरू होती है कि जब लोग साथ आते हैं, खुले तौर पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और सम्मानपूर्वक जुड़ते हैं, तो प्रगति संभव है।' उन्होंने जोड़ा कि स्थायी प्रगति के लिए असहमतियों को 'सम्मान के साथ' संभालना आवश्यक है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने इस रिश्ते को दीर्घकालिक और महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान का यह संबंध निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संबंधों में से एक है, जो लगभग आठ दशकों में कई सफल साझेदारियों के रूप में सामने आया है। हर बार जब हम साथ आए हैं, इसका प्रभाव द्विपक्षीय दायरे से परे रहा है और पूरी दुनिया को लाभ हुआ है।' अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव एस पॉल कपूर ने कहा कि वाशिंगटन ठोस परिणाम चाहता है। 'हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि

अमेरिका-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों में सद्भावना और उच्च-स्तरीय ध्यान अमेरिकी और पाकिस्तानी लोगों के लिए ठोस लाभ में बदलें।' इस संगोष्ठी में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर पैनल चर्चाएं हुईं। विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय स्थिरता, जिसमें भारत व चीन के साथ पाकिस्तान के संबंध भी शामिल हैं और व्यापार व निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया। माइकल कगलमैन (अटलांटिक काउंसिल) ने कहा कि यह साझेदारी 'अच्छी स्थिति में है,' लेकिन इसे समय के साथ अधिक टिकाऊ बनाने की जरूरत है। पूर्व राजदूत तौकीर हुसैन ने चेतावनी दी कि अमेरिकी नीति केवल दिखावे से आगे बढ़नी चाहिए। 'अगर अमेरिका अच्छे साझेदार चाहता है, तो उसे अच्छी नीतियां बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी नीति का मापदंड केवल यह नहीं होना चाहिए कि वह वाशिंगटन में अच्छी दिखती है। सुरक्षा चिंताएं भी प्रमुख मुद्दा रहीं। लीसा कर्टिस ने चेतावनी दी कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) अब भी 'एक खतरनाक और घातक संगठन' है और पाकिस्तान की स्थिरता सुनिश्चित करने में अमेरिका की रुचि पर जोर दिया। हसन अब्बास ने आतंकवाद, संगठित अपराध और सीमा-पार खतरों से निपटने के लिए नागरिक कानून-प्रवर्तन को मजबूत करने की आवश्यकता बताई।

आर्थिक मोर्चे पर सोफयां युसूफी ने पाकिस्तान में डिजिटलीकरण और व्यापक आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ते प्रयासों का उल्लेख किया लेकिन निर्यात और विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए स्पष्ट औद्योगिक नीति की जरूरत बताई। एसपेरेंजा (यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स) ने कहा कि नए सिरे से जुड़ाव ने निजी क्षेत्र के निवेश के अवसर खोले हैं और द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों को सुलझाने का आह्वान किया।

अंत में सुओज़ी ने कहा, 'यह सम्मेलन अतीत से सीखने, वर्तमान को समझने और हमारे दोनों देशों के बीच अधिक समझदारी व सहयोगपूर्ण भविष्य का मार्ग तैयार करने के बारे में है।'

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

हाइब्रिड इवैल्यूएशन सिस्टम का ऐलान, किसी भी छात्र को नहीं होगा नुकसान

सीबीएसई का ये नया ग्रेडिंग सिस्टम बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स के औसत पर आधारित

नई दिल्ली ।

मिडिल ईस्ट में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते तनाव के कारण इस साल सीबीएसई को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा था। इसमें बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में रह रहे हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल था कि उनका रिजल्ट कैसे बनेगा या उन्हें किस तरह नंबर दिए जाएंगे? अब इस चिंता को दूर करते हुए सीबीएसई ने हाइब्रिड इवैल्यूएशन सिस्टम 2026 की घोषणा की है। बता दें 16 मार्च से 10 अप्रैल के बीच इन परीक्षाओं का आयोजन होना था, जो युद्ध के चलते बीच में ही रद्द करनी पड़ी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने हाइब्रिड इवैल्यूएशन सिस्टम 2026 का ऐलान करते हुए साफ कहा है कि किसी भी छात्र को शैक्षणिक नुकसान नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि रिजल्ट की घोषणा समय पर की जाएगी। ईरान के साथ इजराइल-अमेरिका युद्ध का असर खाड़ी देशों के छात्रों पर भी देखने को मिल रहा है। पहले तो उनकी परीक्षा स्थगित हुई और फिर रद्द कर दी गई। इसलिए सीबीएसई ने अब नया ग्रेडिंग सिस्टम लेकर आया है, जिससे युद्ध के चक्कर में उनका साल बर्बाद न हो।

रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएसई का ये नया ग्रडिंग सिस्टम बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स के औसत पर आधारित है। ऐसे में जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है, उस पेपर के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। लेकिन वहीं, जिन विषयों के लिए परीक्षा नहीं हुई है, उसके लिए बोर्ड इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल नंबरों के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार करेगा यानी स्कूल में हुए टेस्ट और प्रैक्टिकल के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। बता दें बोर्ड ने कहा है कि स्कूलों को 6 से 13 अप्रैल के बीच सीबीएसई के पोर्टल पर छात्रों के मार्क्स अपलोड करने होंगे। एक बार नंबर अपलोड होने के बाद इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

अभिभावकों और छात्रों की सबसे बड़ी चिंता बोर्ड रिजल्ट की तारीखों को लेकर है, लेकिन बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि खाड़ी देखों का रिजल्ट भारत समेत दुनिया भर के साथ ही घोषित किया जाएगा। इससे छात्रों को

विदेशी या भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में समय रहते आवेदन किया जा सकता है। वहीं, अगर कोई छात्र हाइब्रिड फॉर्मूला से मिले नंबरों से खुश नहीं हैं, तो उन्हें मई-जून में आयोजित होने वाली इंप्रूवमेंट परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा।

सोमनाथ मंदिर में शिखर की जगह अब त्रिशूल का नया लोगो

सोमनाथ ।

सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धाम का लोगो 77 साल बाद बदला गया है। अब मंदिर के पावन शिखर की जगह नए लोगो में भगवान शिव का प्रतीक त्रिशूल दर्शाया जाएगा। सोमनाथ ट्रस्ट ने इस बदलाव को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। नया लोगो पहली अप्रैल से ट्रस्ट के सभी आधिकारिक पत्राचार, साइन बोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगा। ट्रस्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और विभिन्न धार्मिक आयोजनों के प्रचार में भी इस नए प्रतीक का उपयोग शुरू कर दिया है। ट्रस्ट के अनुसार, त्रिशूल भगवान शिव की शक्ति, संरक्षण और आस्था का प्रतीक है, जो सोमनाथ की पहचान को और सशक्त बनाएगा। श्रद्धालुओं के बीच भी इस नए लोगो को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है।

सूरत में फर्जी पेट्रोल पंप का हुआ भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

अमरोली इलाके में चाय की टपरी के पास चल रहा था अवैध धंधा, 800 लीटर घटिया डीजल व टैंकर जब्त

सूरत।

गुजरात के सूरत में पुलिस ने अवैध रूप से संचालित एक फर्जी पेट्रोल पंप का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शहर के अमरोली इलाके में की गई, जहां चाय की एक टपरी के पास लंबे समय से सस्ते दामों पर घटिया गुणवत्ता का डीजल बेचा जा रहा था।

पुलिस के अनुसार, अमरोली-वेलंजा रोड स्थित अंजनी इंडस्ट्रीज कैनाल के पास आरोपियों ने अवैध रूप से पेट्रोल पंप जैसा सेटअप तैयार कर रखा था। यहां ग्राहकों को कम कीमत का लालच देकर खराब क्वालिटी का डीजल बेचा जाता था। मामले की

जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और पूरे रैकेट का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से करीब 800 लीटर डीजल जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 61,600 रुपये बताई गई है। इसके अलावा दो टैंकर और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 22.70 लाख रुपये आंकी गई है। इस मामले में 43 वर्षीय भरत केरासिया और 32 वर्षीय महेश खिसडिया को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि इस अवैध कारोबार में दो अन्य लोग भी शामिल हैं, जो फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

खाड़ी युद्ध से गहराते पेट्रोलियम संकट के बीच यूपी में गोबर गैस बनेगी राहत का जरिया

नई दिल्ली।

मध्य पूर्व में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल पैदा कर दी है। युद्ध की इन परिस्थितियों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बाधित होने का खतरा मंडरा रहा है। इस संभावित संकट को भांपते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है। सरकार की योजना प्रदेश भर की गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट (बायोगैस) स्थापित कर एलपीजी रसोई गैस का एक ठोस विकल्प तैयार करने की है।इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में संचालित सभी 7,527 गौशालाओं और गो-आश्रय स्थलों को ऊर्जा उत्पादन के केंद्रों में बदला जाएगा। वर्तमान में राज्य के इन केंद्रों में लगभग 12.39 लाख गोवंशीय पशु मौजूद हैं। अब तक इन गौशालाओं से प्राप्त गोबर का मुख्य उपयोग केवल जैविक खाद या कंपोस्ट बनाने तक सीमित था, लेकिन अब इसके एक-एक अंश का उपयोग ईंधन उत्पादन के लिए किया जाएगा। वर्तमान में 80 बड़ी गौशालाओं में बायोगैस प्लांट पूरी तरह क्रियाशील हैं, जिन्हें सफलता के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को मिशन मोड पर चलाने के निर्देश दिए हैं। योजना का उद्देश्य न केवल ईंधन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को रसोई गैस की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से राहत दिलाना भी है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी। रणनीति के अनुसार, पहले चरण में सरकारी और संरक्षित गौशालाओं में प्लांट लगाए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में व्यक्तिगत पशुपालकों को भी इस दायरे में लाया जाएगा।

राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका राजकुमारी मारु का निधन

जयपुर ।

राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती राजकुमारी मारु का 80 वर्ष की उम्र में बीकानेर में निधन हो गया, इससे संगीत और साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। शनिवार सुबह 9:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा गंगाशहर स्थित निवास से निकली और नोखा रोड के नागरिक परिषद मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें अनेक गणमान्य नागरिकों, साहित्यकारों और संगीतज्ञों ने भावभीनी विदाई दी। 15 अक्टूबर 1945 को जन्मी राजकुमारी मारु ने शिक्षा और संगीत दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में एम.ए. के साथ संगीत विशारद और संगीत भास्कर की उपाधियां प्राप्त कीं। वे राजस्थान शिक्षा विभाग में वरिष्ठ व्याख्याता के पद से सेवानिवृत्त हुईं। संगीत के क्षेत्र में वे आकाशवाणी की 'बी-हाई ग्रेड' कलाकार रहीं और उनके लोकगीत, भजन, मंचों, टीवी और रेडियो पर लंबे समय तक लोकप्रिय रहे। उनकी भजन सीडी 'भैरूं मतवाला' और 'राम रूणीचे वाला' विशेष रूप से जनप्रिय रहीं। उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। वर्ष 1993 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का 'कला पुरोधा सम्मान' (2022-23), करणी माता सम्मान, अल्लाह जिलाई बाई अवार्ड और गोपाल गोस्वामी पुरस्कार सहित अनेक सम्मान उन्हें प्राप्त हुए। संगीत के साथ-साथ उन्होंने साहित्य में भी योगदान दिया।

अमरावती को आंध्रप्रदेश की राजधानी बनाने विधानसभा में पेश हुआ प्रस्ताव

सीएम नायडू ने सभी सदस्यों से अपना पूर्ण समर्थन देने का किया आग्रह

अमरावती।

आंध्रप्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को विधानसभा में एक अहम प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार से अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता देने का आग्रह किया। विधानसभा का यह सत्र विशेष रूप से अमरावती को राजधानी के रूप में कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग वाले प्रस्ताव पर चर्चा करने और इसे बुलाया गया था, जो राजधानी शहर के मुद्दे पर स्पष्टता और स्थिरता लाने की दिशा में एक अहम कदम है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने संबोधन में सीएम नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि राजधानी के मुद्दे पर कानूनी निश्चितता आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में उचित संशोधनों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। विधानसभा ने भारत सरकार से अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करने का अनुरोध करने का संकल्प लिया। यह संशोधन अमरावती में शब्द जोड़कर और स्पष्टीकरण का

विस्तार करके किया जाएगा, ताकि यह साफ हो सके कि अमरावती में वे क्षेत्र शामिल हैं जो आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

असम में चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस एक ही कम्युनिटी की पार्टी बन जाएगी: सीएम सरमा

गुवाहाटी।

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर सिर्फ एक समुदाय की पार्टी होने का आरोप लगाया। हिमंता ने कहा कि करीब 99 फीसदी हिंदू कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। राज्य में इसके टूटने का प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। नतीजों के बाद कांग्रेस एक ही कम्युनिटी की पार्टी बन जाएगी। असम में 9 अप्रैल को सिंगल फेज में चुनाव हैं। 30 मार्च को पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए एक रैली को वर्चुअली संबोधित करेंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य बीजेपी ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से इस अनोखी और इंटरैक्टिव पहल में हिस्सा लेने के लिए ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करने की बात कही है।

पहुंची विदेशी पर्यटक की खाना खाने के बाद मौत

सवाई माधोपुर ।

राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर में सफारी करने के कुछ घंटे बाद एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई। आयरलैंड की निवासी टूरिस्ट एक ग्रुप के साथ घूमने आई थी। गुरुवार रात को होटल में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप के बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। टूरिस्ट का पोस्टमॉर्टम आयरलैंड एम्बेसी के अप्रूवल के बाद ही होगा। कुण्डेरा थाने के एएसआई ने बताया कि आयरलैंड की मरियन फ्रांसिस (40) दोस्तों के साथ 25 मार्च को रणथंभौर आई थी। उनका ग्रुप हेरिटेज हवेली होटल में रुका था। सभी ने 26 मार्च को सुबह-शाम के स्लॉट में सफारी की थी। इसके बाद वे होटल आ गए थे। गुरुवार देर रात खाने के बाद करीब 2.30 बजे मरियन की तबीयत बिगड़ी थी। मरियन के दोस्तों ने होटल स्टाफ को सूचित किया। इसके बाद मरियन को अपेक्स सेविका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रात करीब तीन बजे मरियन को सवाई माधोपुर के जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। इस दौरान पुलिस भी निजी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। पुलिसकर्मियों के साथ मरियन के दोस्त उन्हें सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने मरियन की जांच की। कुछ देर बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया।

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस में बगावत, पार्टी छोड़ सकते हैं विधायक

कांग्रेस ने पांच विधायकों को जारी किए नोटिस, 30 को दिल्ली में बैठक

नई दिल्ली।

हरियाणा में हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनावों के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह और बगावत खुलकर सामने आ गई। क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर पार्टी द्वारा उठाए गए सख्त कदमों के बाद अब कई विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। हरियाणा में 16 मार्च को राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान हुआ था। कांग्रेस ने कर्मवीर सिंह बौद्ध को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को अपना समर्थन दिया था।

इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध को एक वोट से जीत मिली, लेकिन कांग्रेस के पांच विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और इसके चलते बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को 27 वोट मिले थे। इस मामले में कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वाले पांच विधायकों को नोटिस जारी किया। इस नोटिस के बाद विधायकों ने बागी तेवर अपना लिए हैं और पार्टी में फूट पड़ने की नौबत आ गई है। जिनको नोटिस दिया गया है इनमें से चार के नाम पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने 18 मार्च को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक किए जिनमें शैली चौधरी, रेनू बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल के नाम शामिल हैं। पांचवें विधायक का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसमें रतिया के जरनैल सिंह का भी जिक्र था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस पाने वाले विधायकों में से मोहम्मद इलियास ने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी और शुक्रवार को वह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिलने गए थे। खट्टर को लेकर माना जाता है कि अब भी उनका हरियाणा बीजेपी पर होल्ड है और उनकी सलाह पर ही सीएम सैनी अहम फैसले लेते हैं। ऐसे में लगातार दो मुलाकातों के चलते चर्चा है कि इलियास कांग्रेस छोड़ सकते हैं। वहीं मोहम्मद इजराइल का कहना है कि मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार ही पसंद नहीं था। दो अन्य विधायकों का कहना है कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की है।

इस बीच शुक्रवार को साढौरा से कांग्रेस विधायक रेनू बाला ने पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। रेनू बाला ने अपने ऊपर लगे क्रॉस-वोटिंग के आरोपों को भ्रामक और उनके खिलाफ चलाए जा रहे एक प्रेरित अभियान का हिस्सा बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने पार्टी के निर्देशानुसार कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध को ही वोट दिया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपना मतपत्र कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा को दिखाया था, जो वोट सत्यापित करने के लिए अधिकृत थे।

रेनू बाला के साथ ही नोटिस पाने वाले पांच विधायकों में से कुल तीन ने अपना जवाब दे दिया है। नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी और रतिया के विधायक जरनैल सिंह ने भी अपना जवाब दाखिल करते हुए क्रॉस-वोटिंग से इनकार किया और दावा किया कि उन्होंने भी हुड्डा को अपना बैलेट दिखाया था। पुन्हाना के विधायक

मोहम्मद इलियास और हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल ने अभी तक नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

हथीन विधायक मोहम्मद इजराइल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि जनता तय करेगी कि मैं 2029 का चुनाव लड़ूंगा या नहीं और किस पार्टी से लड़ूंगा। मैंने जो कुछ भी किया, वह आपके और आपके बच्चों के विकास के लिए किया। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने यह फैसला आपके सम्मान के लिए लिया था, न कि किसी संपत्ति के लिए। इन पांचों विधायकों के भविष्य पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति की बैठक होने की संभावना है।

खराब मौसम के कारण 2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा विमान.....शाह थे सवार

नई दिल्ली।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोलकाता पहुंचने वाली फ्लाइट शुक्रवार रात खराब मौसम के कारण करीब 2 घंटे लेट हुई। उनका विमान तय समय 11:46 बजे की बजाय शनिवार तड़के 1:46 बजे उतरा। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, तेज आंधी-बारिश और बिजली गिरने के कारण विमान को नादिया और नॉर्थ 24 परगना के ऊपर काफी देर तक हवा में चक्कर लगाने पड़े। शाह रात 10:46 बजे दिल्ली से रवाना हुए थे और लैंडिंग के बाद 2 बजे होटल पहुंचे। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फ्लाइट भी इसी तरह मौसम की वजह से करीब एक घंटे तक लैंड नहीं कर सकी थी।